सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 32, नई दिल्ली । रविवार, 14 अप्रैल 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए इससे सफलता मिलेगी या तो शिक्षा।

03 आप 14 अप्रैल को देशभर में मनाएगी 'संविधान बचाओ, तानाशाही हटाओ दिवस'
06 घर में घुसकर मारने के बयान पर चुप्पी क्यों
08 प्रधानाचार्य को बिजेड़ी प्रचार केलिए साजिस : बीजेपी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत देश के अनगिनत युवाओं के साथ लूट, आखिर क्यों ?

संजय बांटला

नई दिल्ली। भारत देश में युवा 18 साल का होते ही सबसे पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इधर उधर भागता है, यह बात हम सभी जानते हैं। क्या ऐसे युवाओं को जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं को लूटने और परेशान करने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ही काफी नही जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भी लर्निंग लाइसेंस के बनवाने के समय ही युवा से पक्के लाइसेंस की टेस्ट फीस साथ में जमा करवा रहा है, जहा तक दिल्ली की बात करे अधिकतर युवाओं को दुबारा लर्निंग लाइसेंस बनवाने की आवश्यकता पड़ती है और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लर्निंग लाइसेंस रिन्यू करने की सुविधा नही दी गई है जिस कारण उस युवा को नया लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ता हैं। नया लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए उस युवा से फिर से पक्के लाइसेंस बनवाने के लिए दिए जाने वाले टेस्ट की फीस जो पहले ही ले रखी दुबारा ली जा रही है आखिर कैसा न्याय है यह, बड़ा सवाल?

उसके अलावा लर्निंग लाइसेंस रिन्यू नही होने के कारण दुबारा लर्निंग लाइसेंस बनवाने के बाद उसे फिर से पक्के लाइसेंस बनवाने के लिए दिए जाने वाले टेस्ट के अपॉइंटमेंट लेने के लिए एक महीने का इन्तजार करना पड़ता है क्या यह न्यायिक है, बड़ा सवाल?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से टोलवा प्रार्थना करता है की लर्निन लाइसेंस को कम से कम 2 बार रिन्यू करने की इजाजत दी जाए इससे सड़कों पर अच्छी स्किल वाले युवा ड्राइवर उपल्ब्ध होंगे और उनको बार बार लर्निंग लाइसेंस बनवाते समय लूटना नही पड़ेगा।

आरसी/ ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं देनी होगी 200 रुपये अतिरिक्त फीस

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। 1 अप्रैल, 2024 से राज्य के वाहन चालकों को ई-ड्राइविंग लाइसेंस और ई-पंजीकरण प्रमाणपत्र डिजी लॉकर के माध्यम से ई-मेल पर प्राप्त होगा। अंतरिम बजट घोषणा के तहत परिवहन विभाग अब वाहनों की आरसी और लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड जारी नही करेगा। अब ड्राइवरों को फिजिकल स्मार्ट कार्ड के रूप में लाइसेंस और आरसी ले जाने की जरूरत नहीं होगी। गौरतलब है कि लाइसेंस बनवाने के लिए फीस के दौरान 200 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब स्मार्ट कार्ड, आरसी और लाइसेंस की जगह ई-ड्राइविंग लाइसेंस और ई-रजिस्ट्रेशन मेल पर मिलेगा। जिसके लिए अब शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा यह देखने और सुनने में आ रहा था कि वाहन के रजिस्ट्रेशन से लेकर उसकी आरसी जारी होने और फिजिकल तौर पर स्मार्ट कार्ड आरसी मिलने में काफी वक्त लग जाता है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लेकिन इस बदलाव के बाद अब वाहन चालकों को पहले की तुलना में जल्द ई-आरसी मिल जाएगी। गौरतलब है कि यह बदलाव विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण है. कई जगहों पर आरसी और लाइसेंस के भौतिक दस्तावेजों को ही पुलिस प्रशासन और अन्य विभाग वैध मानते हैं, जिससे इस बदलाव के बाद संबंधित विभागों और पुलिस प्रशासन की ओर से विरोध की आशंका है लेकिन इस सुविधा के बाद वाहन चालकों को संबंधित अधिकारी के ई-हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर के साथ घर बैठे ई-मेल पर आरसी और लाइसेंस मिल जाएगा। विभाग ने वाहन चालकों को सुविधा देने और डिजी लॉकर को प्रभावी बनाने के लिए यह बदलाव किया है।

"हमारे समुदाय को सशक्त बनाना : स्थानीय अधिकारियों का समर्थन करने का आह्वान"

राष्ट्र के प्रिय युवाओं,

हमारे राष्ट्र के भावी संरक्षक के रूप में, यह हमारा दायित्व है कि हम जिन समुदायों में रहते हैं उन्हें आकार देने में अपनी सामूहिक आवाज की शक्ति को पहचानें। हमारे देश की ताकत न केवल इसके संस्थानों की भव्यता में निहित है, बल्कि इसके लोगों की लचीलापन और एकता में भी निहित है, खासकर जमीनी स्तर पर। इसी भावना के साथ मैं आपसे सशक्तिकरण की यात्रा शुरू करने का आग्रह करता हूं, जो हमारे अपने पड़ोस से शुरू होकर हमारी भूमि के सबसे दूर तक फैली हुई है।

हमारी यात्रा एक सरल लेकिन गहन सिद्धांत के साथ शुरू होती है: हमारे स्थानीय अधिकारियों के लिए समर्थन। ये संस्थाएँ-हमारे नगर निगम, प्रशासन विभाग और पुलिस बल-हमारे समाज की आधारशिला हैं। वे हमारे समुदायों की सुरक्षा, भलाई और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात अथक प्रयास करते हैं। फिर भी, अक्सर, उनके प्रयासों पर ध्यान नहीं दिया जाता या उनकी सराहना नहीं की जाती।

अब समय आ गया है कि हम, इस देश के युवा, इस कहानी को बदलें। हमें अपने स्थानीय अधिकारियों को सक्रिय रूप से समर्थन देने की आदत डालनी चाहिए, न केवल शब्दों के माध्यम से, बल्कि ठोस कार्यों के माध्यम से जो हमारे समाज की बेहतरी के लिए हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। चाहे वह सामुदायिक सफाई अभियान के लिए स्वेच्छा से काम करना हो, पड़ोस के निगरानी कार्यक्रमों में भाग लेना हो, या स्थानीय अधिकारियों के साथ रचनात्मक बातचीत में शामिल होना हो, हमारे समुदायों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में हममें से प्रत्येक की भूमिका है।

अपने स्थानीय अधिकारियों का समर्थन करके, हम न केवल अपने समाज के ताने-बाने को मजबूत करते हैं बल्कि एक अधिक समावेशी और भागीदारी वाले लोकतंत्र की नींव भी रखते हैं। हम अपने समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और सकारात्मक बदलाव के अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों और सिविल सेवकों के साथ हाथ से काम करते हुए प्रगति में भागीदार बनते हैं।

लेकिन हमारी यात्रा यहीं ख़त्म नहीं होती. चूँकि हम अपने स्थानीय लोगों के लिए मुखर होने का प्रयास करते हैं, हमें न्याय, निष्पक्षता और जवाबदेही के सतर्क संरक्षक भी बने रहना चाहिए। हमें अपने स्थानीय अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए और पारदर्शिता, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वकालत करनी चाहिए।

आइए हम सब मिलकर सशक्तिकरण की इस यात्रा पर आगे बढ़ें, यह जानते हुए कि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन संभावनाओं से भी भरा हुआ है। आइए हम परिवर्तन के एजेंट बनें जिनकी हमारे समुदायों को ज़रूरत है, सभी के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य की खोज में अपने स्थानीय अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। -डॉ अंकुर शरण

युवा दिमागों को सशक्त बनाना: बाल हनुमान मंडली की प्रेरक यात्रा : डॉ अंकुर शरण

परिवहन विशेष न्यूज

विकर्षणों से भरी दुनिया में, युवा मन में मूल्यों और आध्यात्मिक शिक्षाओं को स्थापित करना सर्वोपरि है। इस आवश्यकता को पहचानते हुए, संस्कारशाला ने बाल हनुमान मंडली की परिवर्तनकारी पहल की शुरुआत की। 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर अपनी शुरुआत के बाद से, यह पहल बच्चों और उनके माता-पिता को हनुमान चालीसा के जाप और समझ के माध्यम से समान रूप से सशक्त बना रही है।

हनुमान चालीसा, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक पवित्र भजन, हिंदू पौराणिक कथाओं में गहरा महत्व रखता है। यह भगवान हनुमान के वीरतापूर्ण कार्यों और अटूट भक्ति का वर्णन करता है, जो व्यक्तियों की आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। बाल हनुमान मंडली के माध्यम से, प्रतिभागी न केवल चालीसा को कंठस्थ करना सीखते हैं, बल्कि हनुमान द्वारा सन्निहित भक्ति और निस्वार्थता के सार को समझते हुए, इसके गहरे अर्थों में भी उतरते हैं।

मंगलवार और शनिवार की सभाओं में बच्चों और माता-पिता का सामंजस्यपूर्ण मिलन देखा जाता है, जो हनुमान चालीसा का जाप करने के लिए एक साथ आते हैं। मधुर संगीत के साथ उनकी आवाज की गूंज सकारात्मकता और शांति से भरा माहौल बनाती है। युवा उत्साह और श्रद्धा के साथ हनुमान की शिक्षाओं को अपनाते हुए इन सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

श्री हनुमान का जीवन सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए एक शाश्वत प्रेरणा है। भगवान राम के प्रति उनका निस्वार्थ समर्पण और अटूट निष्ठा विनम्रता, साहस और सेवा के गुणों का उदाहरण है। बाल हनुमान मंडली के माध्यम से, हमारे देश के युवा इन मूल्यों को आत्मसात करते हैं, एक सामंजस्यपूर्ण समाज को आकार देने में स्वैच्छिकता और परोपकारिता के महत्व को सीखते हैं।

इसके आध्यात्मिक महत्व के अलावा, हनुमान चालीसा का जाप मन और आत्मा के लिए कई लाभ प्रदान करता है। छंदों का लयबद्ध पाठ शांति और आंतरिक शांति की भावना पैदा करता है, तनाव और चिंता को कम करता है। इसके अलावा, प्रत्येक श्लोक में निहित गहन अर्थ बौद्धिक जिज्ञासा को उत्तेजित करते हैं, जिससे प्रतिभागियों का सामान्य ज्ञान और आध्यात्मिक समझ समृद्ध होती है।

जैसे-जैसे बाल हनुमान मंडली फल-फूल रही है, यह युवा पीढ़ी के लिए आशा और ज्ञान की किरण के रूप में काम कर रही है। हनुमान की कालजयी शिक्षाओं को स्थापित करके, यह दयालु और लचीले व्यक्तियों की एक पीढ़ी का पोषण करता है, जो समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए तैयार है।

बाल हनुमान मंडली के सुंदर प्रयास न केवल हनुमान चालीसा के जाप को बढ़ावा देते हैं बल्कि युवाओं में इसके महत्व की गहरी समझ भी पैदा करते हैं। संगीत, मंत्रोच्चार और सामूहिक भागीदारी के माध्यम से, यह एक पवित्र स्थान बनाता है जहां सकारात्मकता और भक्ति पनपती है, युवा दिमागों के आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देती है और हमारे राष्ट्र के लिए एक उज्जवल भविष्य को बढ़ावा देती है।

सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों और युवाओं के अंदर सच्ची भावना और स्वैच्छिकता भी विकसित हुई है, वे अब अधिक समझदार हैं और सर्वोत्तम संभव तरीकों से समुदाय की मदद करने के लिए प्रेरित हैं। राजनीतिक या किसी अन्य इरादे के, बस जप का जादू सीखें और राष्ट्र की सेवा में सर्वश्रेष्ठ मानव बनने के लिए अपने प्रभु से आशीर्वाद मांगें।

ऑफिस-घर की भागदौड़ में इग्नोर हो रहा है बच्चा? वर्किंग मॉम ऐसे करें उनकी परवरिश

ऑफिस, घर और बच्चों के बीच बैलेंस बनाना आसान काम नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास एक सही प्लान है तो आपकी जिंदगी काफी हद तक आसान हो सकती है. यहां हम बता रहे हैं कि आप बिजी होते हुए भी अपने बच्चे की सही परवरिश किस तरह कर सकती हैं.

रुटीन करें फॉलो- अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाएं तो हर काम के लिए समय निकाल सकती हैं. इसका सबसे सही तरीका है कि आप अपना और अपने बच्चों का रुटीन बनाएं और उसे फॉलो करें.

सेल्फकेयर के लिए निकालें समय- जब आप खुद अपना खयाल रख सकेंगी तो अपने परिवार का भी बेहतर तरीके से ध्यान रख पाएंगी. इसके लिए जरूरी है कि आप अपने वर्कआउट, मेडिटेशन, हॉबीज आदि के लिए समय निकालें. इस तरह आप खुश रह सकेंगी और बच्चों के साथ शांति से बर्ताव कर पाएंगी.

खुद को न समझें सुपर मॉम- अगर आप खुद से अधिक उम्मीद रखेंगी तो यह आपके लिए अधिक परेशानी बना सकता है. बेहतर होगा कि आप सुपर मॉम बनने की कोशिश ना करें बल्कि अपनी क्षमता के हिसाब से ही हर काम डील करें.

सपोर्ट सिस्टम बनाएं- यह जरूरी नहीं कि आप हर काम खुद कर लें या ना कर पाने का मलाल मन में पालें, बेहतर होगा कि आप लोगों से मदद लेना सीखें. व्यस्त हों तो दोस्तों, परिवार की सहायता लें. जरूरत होने पर ऑफिस मैनेजर से बात करें या डेकेयर की व्यवस्था कर लें.

मैनेजमेंट सीखें- बच्चे आपका भविष्य हैं लेकिन भविष्य निर्माण के लिए आपको ऑफिस का काम करना भी जरूरी है. ऐसे में हर किसी के लिए प्रायोरिटी प्लानिंग करें, मूवी टाइम निकालें, साथ में खेलें, कम से कम 20 मिनट खुल कर बात करें और हर काम के लिए डायरी मेंटेन करें. आप हर महीने का लिस्ट बनाएं कि कौन सा काम कब कंप्लीट करना है. इस तरह आप शांति से हर काम पूरा कर पाएंगी.

बच्चों को सिखाएं- बचपन से ही बच्चों को सफाई रखना, चीजें सही जगह पर रखना, हाइजीन, लोगों की मदद करना आदि की ट्रेनिंग दें. उन्हें यह भी सिखाएं कि अगर कोई जरूरी बात है या कोई बात या परेशानी शेयर करनी है और आप पास में नही हैं तो मैसेज डालकर या लेटर लिखकर अपनी बात जरूरी आपको बताएं. इस तरह आपके बीच हेल्दी कॉम्यूनिकेशन बना रहेगा.

मुस्कुराहट के साथ करें दिन की शुरुआत- सुबह सुबह अगर आप बच्चों के साथ मुस्कुराहट के साथ बात करेंगी तो उनका दिन पॉजिटिविटी के साथ शुरू होगा और आप दोनों दिनभर खुश रहेंगे. बेहतर होगा कि सुबह सुबह साथ में तैयार हों और गुस्सा या डांट की बजाय हंसते खेलते रेडी हों. इस तरह आप एक बेहतर रुटीन के साथ अपने बच्चों की देखभाल भी कर पाएंगी और मॉम वाली गिल्ट से फ्री होकर काम पर भी जा सकेंगी।

मां बनने की राह में रोड़ा बनती है यह बीमारी, गर्भाशय में दीमक की तरह करती है काम, डॉक्टर से जानें कारण और बचाव

एंडोमेट्रिओसिस बीमारी महिलाओं के गर्भाशय में होती है, जिसमें गर्भाशय के अंदर एंडोमेट्रियम टिश्यू बनता है. एंडोमेट्रियम परत बढ़ने पर गर्भाशय के बाहर की ओर फैलने लगती है. फिर ये धीरे-धीरे अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब या अन्य प्रजनन अंगों तक फैलती है. जोकि, अंडाशय की क्षमता पर असर पड़ता है. अब सवाल है कि यह बीमारी मां बनने में कैसे बनती है बाधा? इस बारे में गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. अमृता साहा ने विस्तार से बताया है....

मां बनना हर महिला के लिए एक सुखद अहसास है. लेकिन, तमाम ऐसी बीमारी हैं जो मां बनने की राह में रोड़ा बनने का काम करती हैं. एंडोमेट्रिओसिस बीमारी इनमें से एक है. यह महिलाओं के गर्भाशय में होती है, जिसमें गर्भाशय के अंदर एंडोमेट्रियम टिश्यू बनता है. एंडोमेट्रियम परत बढ़ने पर गर्भाशय के बाहर की ओर फैलने लगती है. फिर ये धीरे-धीरे अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब या अन्य प्रजनन अंगों तक फैलती है. एंडोमेट्रियम परत के बढ़ने से वजाइना के मुख पर अतिरिक्त कोशिकाओं का विकास भी हो जाता है. जब यह परत फेलोपियन ट्यूब तक फैलती है तो इससे अंडाशय की क्षमता पर असर पड़ता है. जोकि इंफर्टिलिटी का कारण बनता है. क्योंकि स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाता. जब एंडोमीट्रीओसिस शरीर के अंदर के ऑर्गन्स आंतों, किडनी वगैरह को प्रभावित करता है तो उस स्थिति को 'फ्रोजेन पेल्विस' कहा जाता है. अब सवाल है कि यह बीमारी गर्भाशय को कैसे नुकसान पहुचाती है? मां बनने में कैसे बनती है बाधा? इन सवालों के बारे में राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. अमृता साहा ने News18 को विस्तार से बताया है.

क्या होता है फेलोपियन ट्यूब?

डॉ. अमृता साहा के मुताबिक, गर्भाशय के दोनों तरफ ओवरी होती है, और ओवरी गर्भाशय से फैलोपियन ट्यूब द्वारा जुड़ी होती है. एंडोमेट्रिओसिस को लोग पीरियड्स दर्द या गर्भाशय-गांठ कह देते हैं. दुनिया भर में इस बीमारी के ट्रीटमेंट से लेकर लक्षणों की जानकारी की कमी है. यह रोग गर्भाशय में दीमक की तरह है.

एंडोमेट्रिओसिस क्यों होता है?

यह बीमारी बाहरी संक्रमण की वजह से नहीं, बल्कि शरीर की आंतरिक प्रणाली में कमी के कारण होती है. इन वजहों में से एक महिलाओं की खराब जीवनशैली से तनाव में रहना भी एक है. इसके साथ ही एन्डोमीट्रीओसिस की वजह इम्युनिटी खराब रहना, गर्भाशय में अतिरिक्त कोशिकाओं का निर्माण होना या फिर किसी प्रकार के घाव या सर्जरी से भी इसकी वजह हो सकती है.

एंडोमेट्रिओसिस के लक्षण क्या हैं?

मासिक धर्म के दौरान असाहनीय दर्द एंडोमेट्रिओसिस के प्रमुख लक्षणों में से एक है. कई बार यह दर्द पूरे महीने तक रहता है. इसके अलावा, पीठ में दर्द रहना, कंधों में दर्द रहना, जांघों में तेज दर्द होना, डायरिया, कब्ज, यूरिन में खून आना, शरीर के निचले हिस्से में जकड़न, पीरियड्स से पहले मांसपेशियों में खिंचाव या फिर पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना भी शामिल हैं.

इस बीमारी से होने वाली परेशानियां

एंडोमेट्रिओसिस बीमारी से पीड़ित महिलाओं को पेट दर्द रहना सबसे बड़ी परेशानी है. इसके अलावा, हड्डियों में दर्द रहना, चेहरे पर झाइयां, बाल झड़ना या सफ़ेद होना, भूलने लगना, इरिटेट होना, हाई बीपी, किडनी का कमज़ोर होते जाना, आंखों की रोशनी कम होने की परेशानियां होती हैं. वहीं, इस बीमारी से ग्रस्त महिला कंसीव नहीं कर पाती, क्योंकि स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाता है.

एंडोमेट्रिओसिस से ऐसे करें बचाव

डॉ. साहा के अनुसार, शरीर में एंडोमेट्रियोसिस होने की संभावना एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर के बढ़ने के कारण होती है. यदि एंडोमेट्रियल की समस्या हो रही है तो इसे रोक पाना मुश्किल है, इसलिए शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन को कम करके एंडोमेट्रियोसिस होने की संभावना से बचाव किया जा सकता है. दरअसल, एस्ट्रोजन मासिक धर्म चक्र के समय गर्भाशय की लाइनिंग मोटी हो जाती है. इसके लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक दवाओं या गर्भनिरोधक उपचारों के माध्यम से एस्ट्रोजन का लेवल कम किया जा सकता है, लेकिन बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के यह दवाएं नहीं लेनी चाहिए. इसके अलावा, नियमित व्यायाम और कम कैफीन युक्त पदार्थों के सेवन से भी एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम किया जा सकता है. वहीं, इसके इलाज के तौर पर हिस्टेरेक्टॉमी नाम की सर्जरी भी की जाती है. जिसमें गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा को हटाने के साथ-साथ दोनों अंडाशय भी निकाले जाते हैं।

अंबेडकर जयंती विशेष

बाबा साहब के सपनों को पूरा करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार में बाबा साहब के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ का रूप दिया गया है। अनुसूचित जाति व जनजाति के बंधुओं को को सशक्त व स्वावलम्बी बनाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गयीं।

भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हिन्दू मुस्लिम एकता की बात कभी हजम नहीं हुई। महात्मा गांधी की हिन्दू मुस्लिम एकता की बात से उन्हें चिढ़ होती थी। बाबा साहब मानते थे कि हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रयास भ्रामक है। इसी बात को लेकर उनके गांधी से मतभेद थे। महात्मा गांधी आजादी के आन्दोलन के दौरान मुस्लिमों का साथ लेने के लिए हर प्रकार का यत्न कर रहे थे लेकिन दलितों की दुर्दशा की उन्हें फिक्र नहीं थी। गांधी जी मुस्लिमों की तो खूब वकालत करते थे लेकिन दलितों के प्रश्न पर वह चुप्पी साध जाते थे।

जब पूरे देश में भारत को स्वाधीन कराने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी का आन्दोलन चल रहा था उसी समय डा. अम्बेडकर एक बहुत बड़ा समाज जो अपने ही समाज द्वारा उपेक्षित था उसके उत्थान में लगे थे। अम्बेडकर छुआछूत को गुलामी से भी बदतर मानते थे। अम्बेडकर जी कहते थे कि आजादी तो मिल जायेगी लेकिन क्या गारंटी है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसे दलित कहते हैं उसके जीवन में कोई परिवर्तन आयेगा।

बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर प्रखर पत्रकार वरिष्ठ स्तम्भकार व लेखक, महान अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, बैरिस्टर, दलितों के मसीहा और जननेता थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियाँ प्राप्त कीं। इसके अलावा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किया था। इसलिए विश्व के अन्य देशों की राजनीति और समस्याओं से वह भलीभांति परिचित थे। हिन्दू मुस्लिम समस्या पर उनका बहुत ही सूक्ष्म और सटीक विश्लेषण था। बहुत सारे विषयों पर पर उन्होंने अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर बेबाकी से लिखा। आधी अधूरी जानकारी के आधार पर उन्होंने कोई धारणा नहीं बनाई।

बाबा साहब पार्टीशन आफ इण्डिया पुस्तक में लिखते हैं मुसलमान की दृष्टि में हिन्दू काफिर हैं और काफिर सम्मान के योग्य नहीं होता। मुसलमानों को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। मुसलमानों की मुख्य रूचि मजहब में है। उनकी राजनीति मूल रूप से मौलवियों पर निर्भर है। इसी पुस्तक में आगे वह लिखते हैं महमूद ने न केवल मंदिर तोड़े बल्कि उसने जीते गए हिन्दुओं को गुलाम बनाने की नीति ही बना रखी थी। मुस्लिम कानून के अनुसार दुनिया दो पक्षों में बंटी है। दारूल इस्लाम और दारूल हरब। इस्लामी कानून के अनुसार भारत देश हिन्दुओं और मुसलमानों की साझी मातृभूमि नहीं हो सकता।

बाबा साहब ने स्वयं लिखा है भारत में मुस्लिम समस्या है एक बड़ी समस्या है। सन 711 से लेकर इस्लाम का जो इतिहास है वह युद्ध का आक्रमण का और क्रूरतम घटनाओं का है। मुस्लिम आक्रमणकारियों का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य हिन्दू धर्म का विनाश था। कुतुबुद्दीन एवक ने लगभग एक हजार मंदिर गिराए और उनके स्थान पर मस्जिदें बनवाई। अंबेडकर लिखते हैं कि क्या सच्चा मुसलमान भारत को अपनी मातृभूमि मानेगा। बाबा साहब ने आशंका व्यक्त की थी कि भारत के मुसलमान जिहाद केवल छेड़ ही नहीं सकते बल्कि जिहाद की सफलता के लिए विदेशी मुस्लिम शक्ति को सहायता के लिए बुला भी सकते हैं। पहले अफगानिस्तान के आक्रमण के समय यहां के मुसलमानों का व्यवहार कैसा रहा क्या हम उसे भूल जाएं।

आज अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में कुछ लोग दलित मुस्लिम एकता की बात कर दलितों को बरगलाने की कोशिश करते हैं वह अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते।

जब देश का राष्ट्रीय नेतृत्व हिन्दू मुस्लिम एकता की आड़ में मुस्लिम तुष्टीकरण में लगा था उस समय 18 जनवरी 1929 को बहिष्कृत भारत के संपादकीय में बाबा साहब निर्भीकता से लिखते हैं कि मुस्लिम लोगों का झुकाव मुस्लिम संस्कृति के राष्ट्रों की तरफ झुकाव हद से ज्यादा ही बढ़ गया है। मुसलमानों की किसी भी गलती को माफ कर देने की गांधी की इसी प्रवृत्ति के अम्बेडकर कटु आलोचक थे।

1930 से 1940 के दशक में सावरकर, डा.हेडगेवार और अम्बेडकर ये तीन ऐसे महापुरूष थे जिन्होंने इस्लाम, ईसाइयत, हिन्दू धर्म और हिन्दू मुस्लिम एकता पर बड़ी बेबाकी और निर्भीकता से अपना मत सार्वजनिक किया था। बाबा साहब ने इस्लाम और ईसाइयत में ढ़ेरों खामियों गिनाई तो उन्होंने हिन्दू धर्म को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने हिन्दू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए जीवन भर कार्य किया। आम्बेडकर जी ने कहा कि छुआछूत भेदभाव आदि समस्याएं हमारे अपने घर की हैं। उन्हें हम आपस में निपट लेंगे। किन्तु यदि कोई बाहरी अनुचित लाभ उठाकर हमारे अन्दर फूट डालने का प्रयत्न करेगी तो इसे कदापि सहन नहीं किया जायेगा। अम्बेडकर ने समाज के कटु विरोध आलोचना एवं उपेक्षाओं को सहन करते हुए भी अपने निर्धारित मार्ग से हटे नहीं और दलितों को हटने भी नहीं दिया। मुस्लिम समाज द्वारा दिखाए गये प्रलोभनों को ठुकराकर उन्होंने अपने अनुयायियों को बौद्धमत का अंगीकार करने की प्रेरणा दी।

राष्ट्र के लिए अम्बेडकर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। लोग उन्हें यह मानकर पूजते हैं कि उन्होंने संविधान लिखा। यह तो उनके जीवन का एक छोटा हिस्सा है। कुछ लोगों का मानना है कि

उन्होंने ईसाइयत और इस्लाम के प्रस्ताव को अस्वीकार कर बौद्ध धर्म अपनाकर उपकार किया। यह सच्चाई तो है लेकिन अम्बेडकर का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने भारत का एक और विभाजन होने से बचा लिया। अंग्रेजों को जब लगा कि अब भारत पर लम्बे समय तक शासन नहीं किया जा सकता तो उन्होंने दलितों और मुस्लिमों को अलग राष्ट्र की मांग के लिए उकसाया।

उस समय के हमारे देश के नेताओं को अंग्रेजों की यह चाल समझ में नहीं आयी। कांग्रेस के सत्ता के लालची नेताओं ने हड़बड़ी में स्वाधीनता से पहले विभाजन स्वीकार कर लिया। अंग्रेज भारत का एक और विभाजन कराना चाहते थे। दलितों को इसके लिए उकसाया गया। परिणामस्वरूप देश के कुछ हिस्सों में दलितों के लिए अलग देश की मांग भी उठने लगी। लेकिन अम्बेडकर पर अंग्रेजों का जादू नहीं चला। वह अंग्रेजों की चाल समझ चुके थे। बाबा साहब ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठायेंगे जिससे इस राष्ट्र की अस्मिता खतरे में पड़े। भारत का एक और विभाजन होने से बचा लिया।

अम्बेडकर का जीवन बड़ा व्यापक विस्तृत और बहुआयामी था। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि उनका समग्रता में अध्ययन नहीं किया। सभी लोगों ने उनका कोई न कोई एक पक्ष ही देखा। जबकि उन्होंने हिन्दूधर्म पर सबसे बड़ा उपकार किया है। उनका जीवन समग्र समाज के लिए प्रेरणादायी है। इस्लामी कट्टरता का सही व सटीक विश्लेषण अम्बेडकर ने 90 वर्ष पूर्व कर दिया था। आज इतने वर्षों बाद भी बाबा साहब का एक—एक शब्द सत्य प्रतीत हो रहा है। मुसलमान लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते हैं। वह देश से पहले मजहब को महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार में बाबा साहब के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ का रूप दिया गया है। अनुसूचित जाति व जनजाति के बंधुओं को को सशक्त व स्वावलम्बी बनाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गयीं। आज सरकारी योजनाओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियों ने कभी काम नहीं किया। मोदी सरकार गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े समेत समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र को साकार किया है। बाबा साहब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के पक्षधर थे। मोदी सरकार ने 370 को समाप्त किया है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत दलित बाहुल्य गांवों में दलित परिवारों के लिए आवास, सड़कें, बिजली, रोजगार उपलब्ध कराये गये। दलित युवाओं को स्वालंबी बनाने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई गयी। प्रधानमंत्री मोदी ने दलित युवाओं को स्टार्ट अप शुरू करने के लिए देश में पहली बार वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की। देश में पहले से चले आ रहे दलित उत्पीड़न कानून 1989 को प्रधानमंत्री मोदी ने संशोधित करके और अधिक सख्त बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के माध्यम से देश के दलितों में पुर्नजागरण की चेतना को जगाने का भरपूर काम किया और इसके तहत कई काम किये गये। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 125वीं जयन्ती वर्ष समारोह पर 125 रूपए और 10 रूपए के स्मारक सिक्के जारी किए।

प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर 14 अप्रैल 2016 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत रत्न बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई। नोटबंदी के बाद देश बदलने की शुरुआत भीम ऐप से की गयी। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर का लंदन स्थित वह तीन मंजिला बंगला खरीद गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर से प्रेरणा लेते हुए उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए काम कर रहे हैं। यही कारण है कि बाबा साहब के अनुयायी आज नरेन्द्र मोदी के साथ हैं।

- बृजनन्दन राजू

(लेखक सामाजिक समरसता मंच से जुड़े

दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी खबर, एलजी सक्सेना ने बिजली, पानी और मुफ्त बस यात्रा को लेकर लिया ये फैसला

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने राजधानी के लोगों को आश्वासन दिया है कि गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं की जाएगी। एलजी ने लोगों से राजनीतिक निहित स्वार्थों द्वारा फैलाए जा रहे बयानों और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उपराज्यपाल ने अपील की है कि लोगों को गुमराह करने की किसी भी कोशिश को खारिज कर देना चाहिए।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में चले जाने पर जनता को मिल रहीं सुविधाएं बंद हो जाने की अफवाहों पर जनता को ध्यान ने देने की उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने अपील की है। उपराज्यपाल ने कहा है कि एक विशेष राजनीतिक दल के सदस्य और संवैधानिक पद की शपथ लेने वाले मंत्रियों द्वारा भी इस तरह के झूठे और जानबूझकर भ्रामक बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रचारित किया जा रहा है कि मुफ्त पानी और बिजली बंद हो जाएगी। महिलाओं के लिए बस यात्रा बंद कर दी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल न्यायिक हिरासत के तहत जेल में हैं। राजनिवास ने कहा है कि यह भी प्रचार किया जा रहा है कि भविष्य में इन योजनाओं को केंद्र सरकार और उपराज्यपाल रोक देंगें।

अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

इस पर स्थिति साफ करते हुए एलजी सक्सेना ने दिल्ली के लोगों को आश्वासन दिया है कि गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं की जाएगी। एलजी ने लोगों से राजनीतिक निहित स्वार्थों द्वारा फैलाए जा रहे बयानों और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

योजनाओं का भुगतान दिल्ली की समेकित निधि से

उपराज्यपाल ने अपील की है कि लोगों को गुमराह करने की किसी भी कोशिश को खारिज कर देना चाहिए।सक्सेना ने रेखांकित किया कि इन योजनाओं का भुगतान एनसीटी दिल्ली की समेकित निधि से किया जाता है, न कि किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के खाते से। इन योजनाओं को दिल्ली के लोगों द्वारा स्वयं वित्त पोषित किया जाता है, जो करों के माध्यम से एनसीटीडी के समेकित कोष में योगदान करते हैं।

सीएम के जेल जाने के कारण योजना नहीं होगी प्रभावित

उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया है कि उपरोक्त सब्सिडी योजनाएं सरकार की है और किसी भी पद पर बैठे किसी व्यक्ति द्वारा संचालित या उस पर निर्भर नहीं हैं और इसलिए, किसी भी व्यक्ति के जेल में होने के कारण किसी योजना के प्रभावित होने का सवाल ही नहीं उठता है। भारत के संवैधानिक और वैधानिक प्रविधानों के अनुसार इन योजनाओं का बजट दस्तावेज़ में बजटीय आवंटन होता है, जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

सक्सेना ने शहर में नागरिक प्रशासन द्वारा अपनाई गई पहले की स्थिति को दोहराया है कि कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार न्यायिक हिरासत के तहत जेल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी योजना को प्रभावित नहीं करता है।

'जेल से चल रही केजरीवाल सरकार', मुफ्त योजनाओं पर दिल्ली सरकार के मंत्री का आया बयान

एलजी पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार पूरी मजबूती से जेल से चल रही है और सरकार द्वारा जारी सभी मुफ्त योजनाएं जारी रहेंगी। आप ने कहा है कि जब तक केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तब तक जनता के सारे काम होते रहेंगे। आप ने कहा केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से काम नहीं रुकने का वादा किया था।

नई दिल्ली। एलजी पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार पूरी मजबूती से जेल से चल रही है और सरकार द्वारा जारी सभी मुफ्त योजनाएं जारी रहेंगी। आप ने कहा है कि जब तक केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तब तक जनता के सारे काम होते रहेंगे।

आप ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादा भी किया था कि वो जेल के बाहर हों या अंदर, काम नहीं रुकने देंगे। दिल्ली की जनता को फ्री बिजली, पानी, शिक्षा और इलाज समेत अन्य सुविधाएं मिलती रहेंगी।

आप नेता और दिल्ली कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीएम केजरीवाल के जेल जाने के बाद जो बोलते थे कि जेल से सरकार नहीं चलने देंगे, अब उन्होंने भी हार मान ली है कि केजरीवाल सरकार जेल से चलेगी और काम होते रहेंगे। उन्होंने इसे केजरीवाल और दिल्लीवालों की जीत बताई है।

मुफ्त सुविधाएं चलती रहेंगी

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में चले जाने पर जनता को मिल रहीं सुविधाएं बंद हो जाने की अफवाहों पर जनता को ध्यान ने देने की उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने अपील की है। उपराज्यपाल ने कहा है कि एक विशेष राजनीतिक दल के सदस्य और संवैधानिक पद की शपथ लेने वाले मंत्रियों द्वारा भी इस तरह के झूठे और जानबूझकर भ्रामक बयान दिए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह प्रचारित किया जा रहा है कि मुफ्त पानी और बिजली बंद हो जाएगी। महिलाओं के लिए बस यात्रा बंद कर दी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल न्यायिक हिरासत के तहत जेल में हैं। राजनिवास ने कहा है कि यह भी प्रचार किया जा रहा है कि भविष्य में इन योजनाओं को केंद्र सरकार और उपराज्यपाल रोक देंगें।

दक्षिण एवं दक्षिण पुर्वी दिल्ली में इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांडर प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत

परिवहन विशेष नई दिल्ली,मोनिका;

नई दिल्ली। सेन्ट जोहन एम्बुलेंस ब्रिगेड की दक्षिण पुर्वी दिल्ली की कालकाजी कोर्प्स के सदस्यों व अधिकारियों की सिद्धार्थ पब्लिक स्कुल गोविन्द पूरी पर एक मीटिंग का आयोजन हुआ जिंसमे जिला स्तर पर संस्था की बेहतरी व स्थानीय निवासियों में इमरजेंसी के दौरान किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति के जीवन की रक्षा किस प्रकार की जाये इस प्रशिक्षण को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाये । इसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाने का प्रस्ताव रक्खा गया । इस मौके पर जिला के असिस्टेंट कमिशनर श्री पी डी वर्खिया ने सदस्यो को प्रशिक्षण देने व सभी सदस्यों के एरिया अलग अलग कैम्प आयोजित करने का आश्वासन दिया। कालकाजी एम्बुलेंस कोर्प्स की कोर्प्स ऑफिसर की अगुवाई में सभी सदस्यों श्री वर्खिया जी का धन्यवाद दिया । मीटिंग में श्रीमती ज्योति शर्मा नर्सिंग सार्जेंट हरकेश नगर ओखला, श्रीमती मंजू तंवर नर्सिंग सार्जेंट छतरपुर क्षेत्र दक्षिणी दिल्ली, कैडेट सार्जेंट श्री यस ठाकुर, एवं सात सदस्य उपस्थित रहे।

नवरात्रों में कालका माता पर आने वाले भक्तों के लिए शुरु स्वास्थ्य देखभाल

परिवहन विशेष कालकाजी नई दिल्ली, मोनिका

नवरात्रि के मौके पर दिल्ली के कालकाजी मन्दिर पर सेन्ट जोहन एम्बुलेंस ब्रिगेड के द्वारा मन्दिर पर आये श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिये दिल्ली पुलिस के आग्रह पर श्रीमती मोनिका कोर्प्स ऑफिसर दक्षिण पुर्वी दिल्ली कालकाजी जॉन के नेतृत्व में फ़र्स्ट ऐड पोस्ट का आयोजन किया गया। जिंसमे एम्बुलेंस ऑफिसर श्री चंदन, नर्सिंग सार्जेंट श्रीमती ज्योति शर्मा, सार्जेंट श्री यश ठाकुर, नर्सिंग सदस्य श्रुति गोस्वामी सेवा में रहे।

'शरथ रेड्डी ने कुल 12 बयान दिए, किसी में भी के. कविता का कभी नाम नहीं लिया', आप का बीजेपी पर हमला

आप की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि सीबीआई ने कुछ अखबरों में फर्जी खबर छपवाई है कि के. कविता ने आम आदमी पार्टी को 25 करोड़ रुपये देने के लिए शरथ रेड्डी को मजबूर किया था।सबको पता है कि रेड्डी ने कुल 12 बयान दिए थे और किसी में भी उसने के. कविता का कभी नाम नहीं लिया है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर फर्जी जानकारी लीक कर इसे सार्वजनिक करने का आरोप लगाया है। आप की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि दो साल की जांच के बाद भी तथाकथित शराब घोटाले में ईडी-सीबीआई को एक चवन्नी का सुबूत नहीं मिला है। इसलिए अब ये एजेंसियां फर्जी जानकारी प्लांट कर रहीं हैं। उन्होंने इस संबंध में प्रकाशित एक खबर को फर्जी बताते हुए कहा कि सीबीआइ ने कुछ अखबरों में फर्जी खबर छपवाई है कि के. कविता ने आम आदमी पार्टी को 25 करोड़ रुपये देने के लिए शरथ रेड्डी को मजबूर किया था।सबको पता है कि रेड्डी ने कुल 12 बयान दिए थे और किसी में भी उसने के. कविता का कभी नाम नहीं लिया है। यह साफ दिख रहा है कि भाजपा की जांच एजेंसियां फर्जी न्यूज प्लांट करके केवल केजरीवाल के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं।

तेज हवा के साथ अचानक बदला मौसम, दिल्ली-NCR में बूंदाबांदी; IGI एयरपोर्ट पर 17 फ्लाइट्स हुईं डाइवर्ट

दिल्ली-एनसीआर में अचानक से मौसम बदल गया है। नोएडा गुरुग्राम गाजियाबाद और दिल्ली सहित आसपास के शहरों में तेज हवा चल रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं जिससे तापमान में गिरावट आई है। तेज धूप के साथ बढ़ती गर्मी से राहत मिली है।

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में अचानक मौसम बदल गया है। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और दिल्ली सहित आसपास के शहरों में तेज हवा चल रही है। कुछ इलाकों में बारिश भी हो रही है। इसके साथ ही खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर 17 फ्लाइट डाइवर्ट की गईं।

मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जिससे तापमान में गिरावट आई है। लोगों को तेज धूप के साथ बढ़ती गर्मी से राहत मिली है।

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के साथ बहादुरगढ़, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद के कई स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश के साथ अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। साथ ही 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। राजस्थान के अजमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर और जोधपुर में भी धूलभरी आंधी के साथ बारिश की संभावना है।

दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री से. दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। वहीं, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

कल कितना था तापमान

12 अप्रैल दिनभर खिली रही तेज धूप के चलते शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले बुधवार को 39.1 डिग्री रहा था। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 21.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

खराब मौसम के कारण फ्लाइट डाइवर्ट

खराब मौसम के कारण 17 फ्लाइट्स भी डाइवर्ट की गईं। उड़ानों का डायवर्जन दोपहर तीन बजे से साढ़े चार बजे तक रहा। अधिकारी ने बताया कि खराब मौसम के कारण अब तक 17 उड़ानों (सात इंडिगो, दो विस्तारा, छह एयर इंडिया, एक एयर इंडिया एक्सप्रेस) को डायवर्ट किया गया है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGI Airport Delhi) हर दिन लगभग 1,300 उड़ानों की आवाजाही संभालता है।

आप 14 अप्रैल को देशभर में मनाएगी 'संविधान बचाओ, तानाशाही हटाओ दिवस', कार्यकर्ता लेंगे शपथ

आम आदमी पार्टी 14 अप्रैल को डॉ. बी आर अंबेडकर की जयंती पर देश भर में संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस मनाएगी। गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे और देश के संस्थापक दस्तावेज को बचाने की शपथ लेंगे। राय ने बताया कि देश के 24 राज्यों की राजधानी में यह आयोजन किया जाएगा।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी रविवार को देशभर में 'संविधान बचाओ, तानाशाही हटाओ दिवस' मनाएगी। आप के दिल्ली प्रमुख और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा कि पार्टी 14 अप्रैल को डॉ. बी आर अंबेडकर की जयंती पर देश भर में 'संविधान बचाओ, तानाशाही हटाओ दिवस' मनाएगी। राय ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे और देश के संस्थापक दस्तावेज को बचाने की शपथ लेंगे।

राय ने बताया कि देश के 24 राज्यों की राजधानी में यह आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर सुबह 11 बजे सभी मंत्री, विधायक समेत पदाधिकारी एकत्र होंगे और बाबा साहब के संविधान की मूल भावना प्रस्तावना को एक साथ पढ़कर शपथ लेंगे।

मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल कर दें: गोपाल राय

उन्होंने कहा कि जेल से सीएम केजरीवाल ने भेजे अपने संदेश में कहा है कि संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए मैं मोदी जी के हर अत्याचार को बर्दाश्त कर लूंगा। इसलिए अब वो वक्त आ गया है, जब देशभर के लोग एक होकर संवैधानिक मूल्यों पर हमला कर रही मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल कर दें।

मंत्री राय ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार हमारे लोकतंत्र और संविधान पर हमला कर रही है।इसका मुकाबला करने के लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आप कार्यकर्ता अपने राज्यों में पार्टी कार्यालयों में इकट्ठा होंगे और हमारे लोकतंत्र और संविधान को बचाने की शपथ लेंगे।

केजरीवाल ने जेल से भेजे विधायकों को संदेश

आप नेता ने कहा कि यह कार्यक्रम देश भर के राज्यों की राजधानियों में पार्टी कार्यालयों में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम केजरीवाल की सलाह पर हो रहा है। राय ने कहा कि जेल से एक अन्य संदेश में केजरीवाल ने आप विधायकों और वालेंटियर्स से यह सुनिश्चित करने के लिए काम करने को कहा कि दिल्ली के लोगों को कोई समस्या न हो।

संविधान बचाने का लेंगे संकल्प

राय ने कहा कि 14 अप्रैल को देश भर के सभी आप कार्यकर्ता संविधान निर्माता अंबेडकर के पोस्टर या तस्वीरों के सामने इकट्ठा होंगे और संविधान बचाने का संकल्प लेंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अब खत्म हो चुकी दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लार्न्डिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

आम आदमी पार्टी ने इस अधिनियम को केंद्र सरकार द्वारा एजेंसियों का दुरुपयोग करार देते हुए दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किया है।

लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गिरोह के सात सदस्य कोर्ट से बरी, दुकान के बाहर फायरिंग मामले में फैसला

परिवहन विशेष न्यूज

पश्चिमी दिल्ली में ज्वेलरी की दो दुकानों के बाहर हुई फायरिंग के मामले में लारेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गिरोह के सात सदस्यों को दिल्ली कोर्ट ने बरी कर दिया है। आरोपित विकास ऋषि राज नरेश यादव मनजीत हरीश ब्रजेश और परविंदर को क्लीन चिट दी गई है। जांच एजेंसी ने आरोपितों की लिखावट के नमूने पेश करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

नई दिल्ली। ज्वेलरी की दो दुकानों के बाहर हुई फायरिंग के मामले में लारेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गिरोह के सात सदस्यों को दिल्ली कोर्ट ने बरी कर दिया है। आरोपित विकास, ऋषि राज, नरेश यादव, मनजीत, हरीश, ब्रजेश और परविंदर को क्लीन चिट दी गई है।

साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की आलोचना करते हुए कहा है कि तीन साल से अधिक समय होने के बाद भी जांच एजेंसी ने आरोपितों की लिखावट के नमूने पेश करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

ज्वेलरी की दुकान के बाहर हुई फायरिंग के मामले में 23 जून 2020 को नजफगढ़ थाना में एफआइआर दर्ज कराई गई थी जिसमें शिकायतकर्ता विजय मेहता ने बताया था कि गहना ज्वेलरी की दुकान के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने फायरिंग की थी और फरार हो गए थे।

बिश्नोई और काला जठेड़ी गिरोह के आठ सदस्य गिरफ्तार

चेहरा पर मास्क लगा होने से वह उन्हें पहचान नहीं सके। इस घटना के 15 मिनट बाद पीसी ज्वेलर के बाहर भी फायरिंग की घटना हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी समेत अन्य तरीकों से मामले की जांच-पड़ताल की। इसके बाद टीम ने लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपितों की लिखावट के नमूने पेश नहीं कर पाए

फिर पुलिस ने 31.08 2020 को द्वारका कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें उसे आरोपितों की लिखावट के नमूने पेश करने थे। तीन साल का समय बीतने के बाद भी पुलिस यह नमूने नहीं पेश कर पाई। वहीं अब कोर्ट ने लारेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गिरोह के सात सदस्यों को बरी कर दिया।

साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले को इस उम्मीद में अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रखा जा सकता कि जांच एजेंसी अपनी नींद से जागेगी और विश्वसनीय सबूत इकट्ठा करने के लिए कदम उठाएगी।

सीएम केजरीवाल को जेल में प्रताड़ित किया जा रहा, उनके अधिकार तक छीन लिए गए', AAP सांसद संजय सिंह का बड़ा

आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर आज जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ति और अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेल में मुख्यमंत्री को मिले अधिकार केंद्र ने छीन लिए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस वजह से सीएम केजरीवाल की पत्नी और परिवारवाले काफी चिंतित हैं।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ति और अपमानित करने का बड़ा आरोप केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया है। आप नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रेसवार्ता कर कहा है कि जेल में मुख्यमंत्री को मिले अधिकार केंद्र ने छीन लिए हैं।

जेल प्रशासन ने सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और भगवंत मान को कांच की दीवार के आर-पार से ही मिलने की अनुमति दी है।जबकि यह नियमों केखिलाफ है। क्योंकि जेल प्रशासन के पास आमने-सामने बैठाकर मुलाकात कराने का अधिकार है।उन्होंने कहा कि जेल का नियम 602 और 605 यह कहता है कि किसी की भी मुलाकात आमने-सामने कराई जा सकती है और यह अधिकार जेल प्रशासन को होता है।

CM का मनोबल तोड़ना चाह रही सरकार: संजय सिंह

उन्होंने कहा कि तिहाड़ में खूंखार अपराधियों की भी मुलाकात आमने-सामने कराई जाती है। जो काम तिहाड़ जेल के इतिहास में अब तक नहीं हुआ, वो अब मोदी जी की अगुआई में हो रहा है। मोदी सरकार जेल मैनुअल में मिले न्यूनतम अधिकार और सुविधाएं छीनकर अरविंद केजरीवाल का मनोबल तोड़ना चाहती है।

सीएम केजरीवाल के परिवार हैं चिंतित: संजय सिंह

उन्होंने कहा कि इस बार देश की जनता उनके अत्याचार, तानाशाही, जुल्म और अहंकार का जवाब अपने वोट से देगी। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की पत्नी और परिवार चिंतित और परेशान हैं। उनके माता-पिता बीमार हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का हाल-चाल जानने के लिए जब सुनीता केजरीवाल आवेदन करती है तो उनको कहा जाता है कि आप आमने-सामने मुलाकात नहीं कर सकते हैं।

जेवर में 1.42 करोड़ से बनेगा पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल, होंगी ये सुविधाएं

इस स्कूल में 1.42 करोड़ रुपये से हाईटेक भवन के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। शासन की ओर से कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम का चयन कर लिया गया है। जेवर ब्लॉक के स्कूल अभी तक सुविधाओं से अछूते थे। कई स्कूलों में छात्रों को जमीन पर बैठकर पढ़ना होता थालेकिन अब जेवर ब्लॉक के स्कूलों की लगातार छवि बदलती जा रही है।

ग्रेटर नोएडा। परिषदीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों को बेहतर शिक्षा के साथ ही बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जेवर ब्लॉक में जनपद का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल बनेगा। इसके लिए कंपोजिट स्कूल ख्वाजपुर को चुना गया है।

इस स्कूल में 1.42 करोड़ रुपये से हाईटेक भवन के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। शासन की ओर से कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम का चयन कर लिया गया है।

जेवर ब्लॉक के स्कूल अभी तक सुविधाओं से अछूते थे। कई स्कूलों में छात्रों को जमीन पर बैठकर पढ़ना होता था,लेकिन अब जेवर ब्लॉक के स्कूलों की लगातार छवि बदलती जा रही है।

हाल ही में जेवर ब्लॉक में दो पीएम श्री स्कूलों का चयन हुआ है। इस ब्लॉक के चार स्कूल पीएम श्री में चुने जा चुके है। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने के बाद परिषदीय स्कूलों का तेजी से कायाकल्प हुआ है। गौतमबुद्ध नगर को प्रदेश का शो विंडो कहा जाता है।

यहां के परिषदीय स्कूलों को हाईटेक सुविधाओं से लैस बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। ताकि यीडा शहर बसने पर छात्रों को पढ़ाई के लिए अच्छी सुविधाएं और शिक्षा मिल सके।

यह होंगी सुविधाएं

पहले मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल में अभ्युदय कंपोजिट स्कूल में पांच कमरे होंगे। इसमें एक लाइब्रेरी होगी, जिसमें छात्रों को बैठकर पढ़ने के लिए सभी सुविधाएं होंगी। एक कंप्यूटर लैब, साइंस और रोबोटिक्स के बारे में सीखने के लिए एक माड्यूलर कंपोजिट लैब, स्मार्ट क्लासरूम और स्टाफ रूम भी शामिल होंगे।

बाल वाटिका, न्यूट्रिशन गार्डन,वाईफाई और आनलाइन सीसीटीवी मानिटरिंग की सुविधा होगी। साफ-सफाई के लिए कर्मचारी और सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड तैनात होंगे।

एक मल्टीपर्पज रूम होगा,रेनवाटर कलेक्शन सिस्टम, सोलर पैनल भी स्कूल में लगाए जाएंगे। आरओ वाटर प्लांट, हाथ धोने की जगह भी बनाई जाएगी। मिड-डे मील मिलेगा और इसके लिए डायनिंग हाल भी होगा।

स्कूल में अभी छात्रों की संख्या कम

वर्तमान समय में स्कूल में छात्रों की संख्या कम है। कक्षा एक से आठवीं तक 150 छात्र नामांकित है। स्कूल में हाईटेक सुविधाएं होने के बाद छात्र संख्या में भी उछाल आएंगा।

स्कूल की प्रधानाध्यापिका नीलम शर्मा ने बताया कि अब छात्रों को कई नए आयाम मिलेंगे। हाल ही में कई छात्रों का विज्ञान प्रदर्शनी में चयन हुआ था। गणित व विज्ञान प्रयोगशाला बनने से छात्रों को काफी फायदा मिलेगा।

जनपद में पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल जेवर में बनेगा। कंपोजिट स्कूल ख्वाजपुर का चयन कर लिया गया है। 1.42 करोड़ रुपये से स्कूल का निर्माण होगा। नई शिक्षा नीति के तहत लिखित के साथ अब अभ्यास पर भी फोकस किया जा रहा है। छात्रों को सभी सुविधाएं मिलेगी। -

राहुल पंवार,बेसिक शिक्षा अधिकारी

जेवर ब्लाक के स्कूलों की छवि तेजी से बदल रही है। चार पीएम श्री के साथ एक मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल का फायदा भी अब छात्रों को मिलेगा।

– मो.राशिद खान,खंड शिक्षा अधिकारी जेवर

खराब मौसम के कारण नोएडा में अमित शाह का कार्यक्रम रद्द, फोन कर मांगी माफी

गौतमबुद्ध नगर में अमित शाह की रैली का कार्यक्रम रद्द हो गया है। खराब मौसम के कारण यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान फोन कर लोगों को जानकारी दी कि वह आज कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे और उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। फोन से कार्यकर्ताओं को संबोधित करके कहा कि जेवर एयरपोर्ट के जरिए गौतमबुद्ध नगर जिले का विकास तेजी से हो रहा है।

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर में अमित शाह की रैली का कार्यक्रम रद्द हो गया है। खराब मौसम के कारण यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान फोन कर लोगों को जानकारी दी कि वह आज कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे और उन्होंने इसके लिए माफी मांगी।

साथ ही फोन से कार्यकर्ताओं को संबोधित करके कहा कि जेवर एयरपोर्ट के जरिए गौतमबुद्ध नगर जिले का विकास तेजी से हो रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने कानून-व्यवस्था मजबूत करके लोगों को सुरक्षा दी है। अमित शाह नोएडा के सेक्टर-33 में आयोजित जनसभा में आने वाले थे, लेकिन मौसम खराब हो गया। तेज हवा चलने की वजह से टेंट उड़ने लगा था। साथ ही गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई थी।

यूपी में बीजेपी ने बसपा को दिया झटका, दिग्गज नेता ने छोड़ी पार्टी; आप-कांग्रेस के नेताओं ने पहना भगवा

यूपी में गढ़ से तीन बार विधायक रहे पूर्व मंत्री मदन चौहान शनिवार को बसपा छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। जेवर विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2022 में कांग्रेस के टिकट से विधायक का चुनाव लड़ चुके मनोज चौधरी और दादरी विधानसभा से 2022 में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे संजय चेची ने शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया।

नोएडा। भाजपा ने चुनाव से पहले बसपा को झटका दिया है। गढ़ से तीन बार विधायक रहे पूर्व मंत्री मदन चौहान शनिवार को बसपा छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने शनिवार को नोएडा में भाजपा की जनसभा में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

पश्चिमी उप्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेंद्र सिसोदिया व पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा ने उन्हें पटका पहनाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। बसपा के लिए इसे झटका माना जा रहा है। मदन चौहान नोएडा में रहते हैं और गौतमबुद्ध नगर में उनका खासा प्रभाव है। सपा के प्रदेश सचिव बेगराज गुर्जर भी भाजपा में शामिल हो गए।

कांग्रेस-आप के नेता भी भाजपा में शामिल

जेवर विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2022 में कांग्रेस के टिकट से विधायक का चुनाव लड़ चुके मनोज चौधरी और दादरी विधानसभा से 2022 में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे संजय चेची ने शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया। संजय चेची की पत्नी लता सिंह नगर पंचायत बिलासपुर की अध्यक्ष है।

मनोज चौधरी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रह चुकें हैं। दादरी विधायक तेजपाल नागर के साथ मनोज व संजय अपने समर्थकों के साथ नोएडा पहुंचे और भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

अवैध किडनी ट्रांसप्लांट मामले में पकड़े गए पांच बांग्लादेशियों को भेजा गया जेल

गुरुग्राम में अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की छापेमारी के बाद चार अप्रैल को सेक्टर 39 के बाबिल गेस्ट हाउस से पकड़े गए पांच बांग्लादेशियों को शनिवार को जेल भेज दिया गया। इनमें तीन मरीज और दो डोनर शामिल हैं। पांच अप्रैल को सभी को गुरुग्राम नागरिक अस्पताल के आइसीयू में भर्ती कराया गया था।

गुरुग्राम। अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की छापेमारी के बाद चार अप्रैल को सेक्टर 39 के बाबिल गेस्ट हाउस से पकड़े गए पांच बांग्लादेशियों को शनिवार को जेल भेज दिया गया। इनमें तीन मरीज और दो डोनर शामिल हैं। पांच अप्रैल को सभी को गुरुग्राम नागरिक अस्पताल के आइसीयू में भर्ती कराया गया था। इसके बाद तबीयत बिगड़ने पर इन्हें दिल्ली के सफदरजंग रेफर किया गया था।

चार अप्रैल को गुप्त सूचना के बाद मुख्यमंत्री उड़नदस्ता, जिला स्वास्थ्य विभाग और गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 39 के बाबिल गेस्ट हाउस में छापेमारी की थी। इस दौरान पांच बांग्लादेशी पकड़े गए थे। इनकी पहचान किडनी प्राप्तकर्ता मो. अहसानुल , नुरुल इस्लाम, आकिब महमूद और किडनी डोनर शमीम मेहंदी हसन व मो. आजाद हुसैन के रूप में हुई थी।

किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आए थे भारत

ये सभी अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मेडिकल वीजा पर भारत आए थे। पूछताछ में आरोपितों ने बताया था कि रांची का रहने वाला मो. मुर्तजा अंसारी इन सभी को जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण के लिए लेकर गया था। लेकिन वहां 31 मार्च की रात एसीबी जयपुर द्वारा की गई कार्रवाई के बाद मुर्तजा इनको लेकर गुरुग्राम के बाबिल गेस्ट हाउस आ गया।

आरोपियों को भोंडसी जेल भेजा गया

पुलिस ने शुरुआत में इनसे पूछताछ कर नागरिक अस्पताल के आइसीयू में भर्ती कराया था। यहां जयपुर पुलिस ने भी इनके बयान लिए। इसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ने पर सफदरजंग भेज दिया गया। सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अर्जुन देव ने बताया कि पांच दिन बाद शनिवार को सभी को गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया। यहां से इन्हें भोंडसी जेल भेज दिया गया।

दूसरी ओर मास्टरमाइंड मो. मुर्तजा अंसारी को पकड़ने के लिए पिछले दस दिन से छापेमारी कर रही है। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने की प्रक्रिया चल रही है।

चुनाव में व्यक्ति नहीं, मूल्यों की स्थापना का दौर चले

लोकतंत्र के महापर्व पर समझना चाहिए कि हमने जीने का सही अर्थ ही खो दिया है। यद्यपि बहुत कुछ उपलब्ध हुआ है। कितने ही नए रास्ते बने हैं। फिर भी किन्हीं दृष्टियों से हम भटक रहे हैं। भौतिक समृद्धि बटोरकर भी न जाने कितनी रिक्तताओं की पीड़ा सही है।

लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां उग्र से उग्रतर होती जा रही है, पहली बार भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा बन रहा है, कुछ भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं तो कुछ भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात कर रहे हैं। मुसलमान वोटों की राजनीति करने वाले दल अपने घोषणा पत्रों में उनके कल्याण की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों का सशक्तीकरण करने की बचाय उनके तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। कुछ दल देश-विकास की बात कर रहे हैं तो कुछ दल विकास योजनाओं की छिछालेदार कर रहे हैं। किसी भी दल के चुनावी मुद्दे में पर्यावरण विकास की बात नहीं हैं। व्यक्ति नहीं, मूल्यों की स्थापना के स्वर कहीं भी सुनाई नहीं दे रहे हैं। सत्ता और स्वार्थ ने अपनी आकांक्षी योजनाओं को पूर्णता देने में नैतिक कायरता दिखाई है। केजरीवाल जेल से सरकार चलाने की बात करके नैतिक एवं राजनीतिक मूल्यों के आन्दोलन से सरकार बनाने के सच को ही बदनुमा बना दिया है। इसकी वजह से लोगों में विश्वास इस कदर उठ गया कि चौराहे पर खड़े आदमी को सही रास्ता दिखाने वाला भी झूठा-सा लगता है। आंखें उस चेहरे पर सचाई की साक्षी ढूंढती हैं। समस्याओं से लड़ने के लिये हमारी तैयारी पूरे मन से होनी चाहिए।

लोकतंत्र के महापर्व पर समझना चाहिए कि हमने जीने का सही अर्थ ही खो दिया है। यद्यपि बहुत कुछ उपलब्ध हुआ है। कितने ही नए रास्ते बने हैं। फिर भी किन्हीं दृष्टियों से हम भटक रहे हैं। भौतिक समृद्धि बटोरकर भी न जाने कितनी रिक्तताओं की पीड़ा सही है। गरीब अभाव से तड़पा है, अमीर अतृप्ति से। कहीं अतिभाव, कहीं अभाव। जीवन-वैषम्य कहां बांट पाया अपनों के बीच अपनापन। अट्टालिकाएं खड़ी हो रही हैं, बस्तियां बस रही हैं मगर आदमी उजड़ता जा रहा है। पूरे देश में मानवीय मूल्यों का ह्रास, राजनीति अपराध, भ्रष्टाचार, कालेधन की गर्मी, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन, अन्याय, शोषण, संग्रह, झूठ, चोरी जैसे-अनैतिक अपराध पनपे हैं। धर्म, जाति, राजनीति-सत्ता और प्रांत के नाम पर नए संदर्भों में समस्याओं ने पंख फैलाये हैं। हर बार के चुनावों की तरह इस बार भी आप, हम सभी अपने आपको जीवन से जुड़ी अंतहीन समस्याओं के कटघरे में खड़ा पा रहे हैं। कहा नहीं जा सकता कि जनता की अदालत में कहां, कौन दोषी है? पर यह चिंतनीय प्रश्न अवश्य है हम इतने उदासीन एवं लापरवाह कैसे हो गये कि राजनीति को इतना आपराधिक होने दिया? जब आपके द्वार की सीढ़ियां मैली हैं तो अपने पड़ौसी की छत पर गन्दगी का उलाहना मत दीजिए। कोई भी अच्छी शुरूआत सबसे पहले स्वयं की की जानी जरूरी है।

देश के लोकतंत्र को हांकने वाले लोग इतने बदहवास होकर निर्लज्जतापूर्ण कारनामे करेंगे, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चौराहे पर खड़ा आदमी सब कुछ देख रहा है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा कि वह कौन सी राह पकड़े। आम आदमी सरकार ने शराब-शिक्षा में घोटाले किए, दागी चिन्हित भी हुए लेकिन आप सरकार ने भ्रष्टाचार को लेकर दोहरे मापदंड अपना लिए। अपनों द्वारा किया गया भ्रष्टाचार कोई भ्रष्टाचार नहीं, राबर्ट वाड्रा के खिलाफ कुछ नजर नहीं आता और वे चुनाव लड़ने की बात करते हैं। बात केवल कांग्रेस की ही नहीं है, बात राजनीतिक आदर्शों की हैं। जिसकी वकालत करते हुए कभी अन्ना हजारे तो कभी बाबा रामदेव, कभी केजरीवाल तो कभी श्री रविशंकरजी जन-आन्दोलन की अगवाई करते देते थे, अब ना तो ऐसे आन्दोलन होते हैं न ही उन पर विश्वास रहा। हमारे भीतर नीति और निष्ठा के साथ गहरी जागृति की जरूरत है। नीतियां सिर्फ शब्दों में हो और निष्ठा पर संदेह की परतें पड़ने लगें तो भला उपलब्धियों का आंकड़ा वजनदार कैसे होगा? बिना जागती आंखों के सुरक्षा की साक्षी भी कैसी! एक वफादार चौकीदार अच्छा सपना देखने पर भी इसलिए मालिक द्वारा तत्काल हटा दिया जाता है कि पहरेदारी में सपनों का खयाल चोरी को खुला आमंत्रण है।

भाजपा जो हमेशा राजनीतिक शुचिता की बात करती रही, उसकी शुचिता कहां है? कितने दागी एवं अपराधी नेताओं को उसने अपने दल में जगह ही नहीं दी, टिकट तक दे दिया। हो सकता है 400 के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिये भाजपा की कुछ मजबूरियां हो। कमल तो खिलेगा ही, लेकिन उस खिलाहट में मजबूरियों के नाम पर मूल्यों के साथ समझौता नहीं होता तो यह लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने का एक अनूठा उदाहरण होता। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कभी कहा था कि व्यक्ति को अपने जन्म से नहीं बल्कि कर्म से पहचाना जाना चाहिए, यह वाक्य उनके पोते राहुल गांधी पर भी लागू हो रहा है। वे तमाम सुखों एवं सुविधाओं में पले-बढ़े और उन्होंने जीवन में कोई संघर्ष नहीं किया या ये कहें कि जीवन के लिए संघर्ष करने की उनके सामने कोई नौबत नहीं आई। कहते हैं- "जा के पैर न परी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई"। जब आप लोगों की पीड़ा को उसी भाव से महसूस नहीं कर पाते तो दूसरों को आपकी बात पर भरोसा नहीं हो पाता। इस भरोसे को पाने के लिए उस पीड़ा को पहले खुद भुगतना होता है। यही वजह है कि राहुल गांधी सच्ची और ठीक बात कहते हैं तब भी लोग उसे उस सच्चाई के साथ, उस भाव में अंगीकार नहीं कर पाते। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का मौजूदा यह आचरण स्वीकार्य नहीं। पूरा राजनीतिक वातावरण ही हास्यास्पद हो चुका है। यदि हालात नहीं सुधरे तो राजनीतिक दलों की दुर्गति तय है। बदलती राजनीतिक सोच एवं व्यवस्था के मंच पर बिखरते मानवीय मूल्यों के बीच अपने आदर्शों को, उद्देश्यों को, सिद्धांतों को, परम्पराओं को और जीवनशैली को हम कोई ऐसा रंग न दे दें कि उससे उभरने वाली आकृतियां हमारी भावी पीढ़ी को सही रास्ता न दिखा सकें।

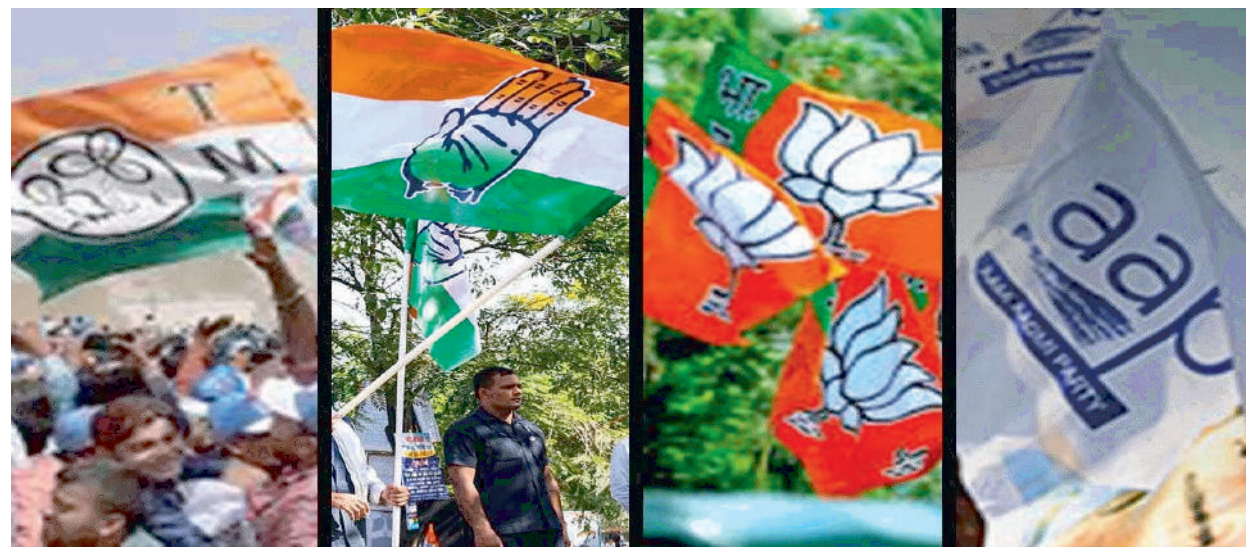

राजनीति का वह युग बीत चुका जब राजनीतिज्ञ आदर्शों पर चलते थे। आज हम राजनीतिक दलों की विभीषिका और उसकी अतियों से ग्रस्त होकर राष्ट्र के मूल्यों को भूल गए हैं। भारतीय राजनीति उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। चारों ओर भ्रम और मायाजाल का वातावरण है। भ्रष्टाचार और घोटालों के शोर और किस्म-किस्म के आरोपों के बीच देश ने अपनी नैतिक एवं चारित्रिक गरिमा को खोया है। मुद्दों की जगह अभद्र टिप्पणियों ने ली है। व्यक्तिगत रूप से छींटाकशी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाठशाला के प्रधानाचार्य की तरह अपने दल के कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ाया कि वह झूठे एवं बेबुनियाद आरोपों की परवाह किए बिना तेजी से काम करें। जबकि विपक्षी दलों की सारी की सारी कवायद में एक अनर्थ सच्चाई के ही दर्शन हुए क्योंकि जैसे केवल चेहरे बदलने से दामन के दाग नहीं धुल जाते, वैसे ही कुछ युवा चेहरों को सामने खड़ा करने से क्रांतिकारी सोच पैदा नहीं की जा सकती। भ्रष्टाचार के मुद्दे को व्यक्तिगत आरोपों की झड़ी लगाकर पृष्ठभूमि में डालने की कोशिश की जा रही है।

कई राजनीतिक दल तो पारिवारिक उत्थान और उन्नयन के लिये व्यावसायिक संगठन बन चुके हैं। सामाजिक एकता की बात कौन करता है। आज देश में भारतीय कोई नहीं नजर आ रहा क्योंकि उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, महाराष्ट्रीयन, पंजाबी, तमिल की पहचान भारतीयता पर हावी हो चुकी है। वोट बैंक की राजनीति ने सामाजिक व्यवस्था को क्षत-विक्षत करके रख दिया है। ऐसा लगता है कि सब चोर एक साथ शोर मचा रहे हैं और देश की जनता बोर हो चुकी हैं। हमें अतीत की भूलों को सुधारना और भविष्य के निर्माण में सावधानी से आगे कदमों को बढ़ाना। वर्तमान के हाथों में जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारियां थमी हुई हैं। हो सकता है कि हम परिस्थितियों को न बदल सकें पर उनके प्रति अपना रूख बदलकर नया रास्ता तो अवश्य खोज सकते हैं। आने वाले नये राजनीतिक नेतृत्व का सबसे बड़ा संकल्प यही हो कि राष्ट्रहित में स्वार्थों से ऊपर उठकर काम करेंगे। राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र सर्वोपरि रहेगा। व्यक्ति का क्या मूल और क्या विसात। विरोध नीतिगत होना चाहिए व्यक्तिगत नहीं। एक उन्नत एवं विकासशील भारत का निर्माण करने के लिये हमें व्यक्ति नहीं, मूल्यों एवं सिद्धान्तों को शक्तिशाली बनाना होगा।

ललित गर्ग

हुंडई क्रेटा ईवी टेस्टिंग के दौरान फिर दिखी, 500 KM की रेंज और इन जबरदस्त फीचर्स के साथ मार सकती है एंट्री

परिवहन विशेष न्यूज

हुंडई मोटर द्वारा क्रेटा एसयूवी के इलेक्ट्रिक वर्जन पर काम करने की खबरें आ रही हैं। पहली बार क्रेटा ईवी का इंटीरियर लुक भी सामने आया है। स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन हाल ही में वैश्विक बाजारों में पेश की गई हुंडई कोना फेसलिफ्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी के समान है। पहले की रिपोर्ट्स से पता चलता है कि हुंडई क्रेटा ईवी कई फीचर्स के साथ आएगी।

नई दिल्ली। काफी दिनों से Hyundai Motor द्वारा Creta SUV के इलेक्ट्रिक वर्जन पर काम करने की खबरें आ रही हैं। पिछले महीने कोरियाई कार निर्माता के होम बेस से सामने आए स्पाई शॉट के बाद, भारतीय सड़कों पर इसका एक फ्रेस टेस्टिंग म्यूल देखा गया है। आइए, क्रेटा ईवी के संभावित डिजाइन और इंटीरियर के बारे में जान लेते हैं।

Hyundai Creta EV का डिजाइन

वीडियो में हुंडई क्रेटा ईवी को ब्लैक कैमोफ्लैग में लिपटे हुए देखा जा सकता है। हालांकि, इसमें 2024 क्रेटा फेसलिफ्ट एसयूवी के साथ आने वाले नए सिग्नेचर एलईडी डीआरएल आसानी से दिख रहे हैं। रूफरेल और टेललाइट यूनिट भी नई क्रेटा एसयूवी के समान हैं।

इंटीरियर

वीडियो में पहली बार क्रेटा ईवी का इंटीरियर लुक भी सामने आया है। स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन हाल ही में वैश्विक बाजारों में पेश की गई हुंडई कोना फेसलिफ्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी के समान है।

यह एक थ्री-स्पोक यूनिट है, जिस पर कई कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। अन्य चीजों में एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रेटा ईवी के इंटीरियर में इसके ICE समकक्षों की तुलना में कई बदलाव होंगे।

फीचर्स

क्लाइमेट कंट्रोल और अन्य फीचर्स के लिए टच-बेस्ड कंट्रोल के साथ इसे फिर से डिजाइन किए गए डैशबोर्ड, नया सेंटर कंसोल और नई Hyundai Kona या Ioniq 5 EV के अंदर देखे जाने वाला डुअल स्क्रीन सेटअप मिल सकता है।

पहले की रिपोर्ट्स से पता चलता है कि Hyundai Creta EV कई फीचर्स के साथ आएगी। इनमें पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री सराउंड कैमरा और लेवल 2 एडास तकनीक शामिल हो सकती है।

बैटरी और रेंज

Hyundai ने Creta EV के आगमन के बारे में अभी तक चुप्पी साध रखी है। इसमें वही इलेक्ट्रिक पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है, जो कोना इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ पेश किया गया है। हुंडई क्रेटा ईवी को लगभग 60 kWh बैटरी पैक से लैस कर सकती है, जिसके एक बार चार्ज करने पर लगभग 450 किलोमीटर की रेंज देने की संभावना है।

जीप रैंगलर फेसलिफ्ट इंडियन मार्केट में 22 अप्रैल को मारेगी एंट्री, पहले से इतनी बदल जाएगी ये ऑफरोडर एसयूवी

Jeep India की ओर से 22 अप्रैल 2024 को Updated Wrangler off-roader को घरेलू बाजार में पेश किया जाएगा। Jeep Wrangler Facelift को ऑल-ब्लैक ट्रीटमेंट मिलेगा और ट्रेडमार्क 7-स्लैट डिजाइन पहले की तुलना में पतला होगा। रैंगलर फेसलिफ्ट में जीप का नवीनतम यूकनेक्ट 5 यूजर इंटरफेस भी मिलेगा जो ऑफ-रोडर के लिए अधिक कनेक्टेड तकनीक लाएगा।

नई दिल्ली। Jeep India की ओर से 22 अप्रैल, 2024 को Updated Wrangler off-roader को घरेलू बाजार में पेश किया जाएगा। जीप रैंगलर फेसलिफ्ट ने लगभग एक साल पहले अपनी वैश्विक शुरुआत की थी और ये एसयूवी भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसकी डिजाइन और फीचर लिस्ट में बड़े अपडेट हुए हैं। आइए, अपकमिंग ऑफरोडर के बारे में जान लेते हैं।

Jeep Wrangler Facelift में क्या खास?

Jeep Wrangler Facelift को ऑल-ब्लैक ट्रीटमेंट मिलेगा और ट्रेडमार्क 7-स्लैट डिजाइन पहले की तुलना में पतला होगा। साथ ही इसमें नए अलॉय व्हील, कई व्हील शेप और रूफ ऑप्शन मिलते हैं। जीप इंडिया संभवतः भारतीय बाजार में सॉफ्ट टॉप और हार्ड टॉप विकल्प लाएगी।

इंटीरियर अपडेट

इसके केबिन में भी सूक्ष्म बदलाव होंगे। इसमें अपडेटेड डैशबोर्ड लेआउट में 12.3 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और रिपोजिशन किए गए एसी वेंट शामिल हैं, जो सभी ट्रिम्स पर स्टैंडर्ड होने वाले हैं।

रैंगलर फेसलिफ्ट में जीप का नवीनतम यूकनेक्ट 5 यूजर इंटरफेस भी मिलेगा, जो ऑफ-रोडर के लिए अधिक कनेक्टेड तकनीक लाएगा। इसके अलावा, सिस्टम में शामिल 62 ऑफ-रोड ट्रेल्स के साथ नई ट्रेल्स ऑफरोड गाइड भी होगी। अन्य अपग्रेड में 12-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल जैसे फीचर्स शामिल होंगे।

इंजन और परफॉरमेंस

जीप रैंगलर फेसलिफ्ट को पावर देने के लिए 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन यूज किया जाएगा, जो 266 बीएचपी और 400 एनएम पीक टॉर्क के लिए ट्यून किया गया है। इस पावरट्रेन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। एसयूवी में जीप सेलेक-ट्रैक फुल-टाइम फोर-व्हील ड्राइव (4WD) सिस्टम भी मिलेगा। आपको बता दें कि भारतीय बाजार के लिए कोई डीजल इंजन नहीं होगा।

संभावित कीमत

रैंगलर वर्तमान में दो वेरिएंट्स - अनलिमिटेड और रूबिकॉन में उपलब्ध है। हमें उम्मीद है कि फेसलिफ्टेड मॉडल पर भी यह जारी रहेगा।

KTM और Husqvarna का ग्राहकों को तोहफा, अब सभी बाइकों पर फ्री में मिलेगी 5 साल तक की एक्सटेंडड वारंटी

KTM और Husqvarna मोटरसाइकिलों को कुल पांच साल और 45000 किमी जो भी पहले हो उसके लिए कवरेज मिलती है। विस्तारित वारंटी अवधि के लाभों में कंपोनेंट और रिपेयर कवरेज कम लेबर चार्ज में 24x7 आरएसए सेफ टोइंग फ्लैट टायर असिस्ट और ऑन-साइट मरम्मत शामिल है। विस्तारित वारंटी कार्यक्रम केटीएम डीलरशिप पर उपलब्ध है और कंपनी का कहना है कि यह केवल सीमित समय के लिए उपलब्ध होगा।

नई दिल्ली। विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से KTM India ने घोषणा की है कि वह 1 अप्रैल, 2024 से अपनी मोटरसाइकिलों पर 5 साल तक की वारंटी कवरेज पेश करेगी। ये Extended Warranty बिना किसी तरह के खर्च पर उपलब्ध होगी।

KTM और Husqvarna दोनों के लिए है ये ऑफर

ये ऑफर KTM और Husqvarna दोनों के प्रोडक्ट्स पर उपलब्ध है। कुल वारंटी कवरेज में स्टैंडर्ड दो साल की वारंटी के साथ-साथ तीन साल की एक्सटेंडेड वारंटी और एक साल का रोड साइड असिस्टेंस शामिल है। KTM का कहना है कि उसका Industry-Leading वारंटी प्रोग्राम वाहन वितरण से परे ग्राहकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाता है।

वारंटी की पूरी डिटेल

KTM और Husqvarna मोटरसाइकिलों को कुल पांच साल और 45,000 किमी, जो भी पहले हो उसके लिए कवरेज मिलती है। विस्तारित वारंटी अवधि के लाभों में कंपोनेंट और रिपेयर कवरेज, कम लेबर चार्ज में 24x7 आरएसए, सेफ टोइंग, फ्लैट टायर असिस्ट और ऑन-साइट मरम्मत शामिल है।

चुनिंदा ग्राहकों को ही मिलेगा लाभ

विस्तारित वारंटी कार्यक्रम केटीएम डीलरशिप पर उपलब्ध है और कंपनी का कहना है कि यह केवल सीमित समय के लिए उपलब्ध होगा। केटीएम रेंज 125 ड्यूक से लेकर 390 एडवेंचर तक है। हुस्कवर्ना रेंज में दो मोटरसाइकिलें- विटपिलेन 250 और स्वार्टपिलेन 401 शामिल हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि मौजूदा केटीएम यूजर मुफ्त में विस्तारित वारंटी के लिए पात्र होंगे या नहीं, खासकर वे जिन्होंने हाल ही में अपनी बाइक खरीदी है।

बीच रास्ते में अचानक बंद हो गई है गाड़ी? जम्प-स्टार्ट करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप

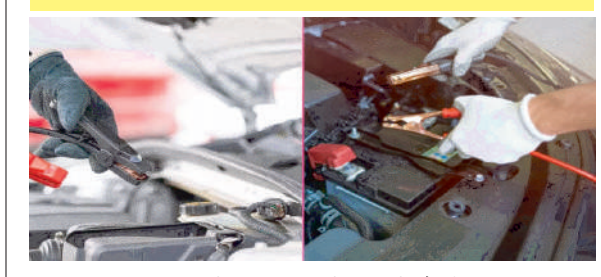

किसी भी कार मालिक के लिए जम्पस्टार्टिंग कोई आम बात नहीं है। हालांकि, कई बार लोग इमरजेंसी में फंस जाते हैं और उस समय उनके सामने कई सारी दिक्कतें होती हैं। अगर कोई वाहन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम उसे जम्पस्टार्ट करने के लिए यहां कुछ आसान से तरीके लेकर आए हैं। आइए, इसे स्टेप-बाय स्टेप जान लेते हैं।

जम्पर केबल लाएं

कार की डिक्की में हमेशा एक जम्पर केबल रखना चाहिए। याद रखें कि आपकी कार एक मशीन है और मशीनें बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी खराब हो सकती हैं। इसलिए हमेशा जम्पर केबल का एक सेट रखें, क्योंकि यदि आपके वाहन को जम्पस्टार्टिंग की आवश्यकता होती है तो यह काम में आएगा।

दूसरी कार अरेंज करें

जब आपको दूसरी चालू कार मिल जाए, तो दोनों वाहनों को न्यूट्रल में पार्क करें और दोनों कारों का इग्निशन बंद कर दें। साथ ही दोनों वाहनों में पार्किंग ब्रेक भी लगा लें।

जम्पर केबल कनेक्ट करें

कार को जम्पस्टार्ट करने के लिए आपको जम्पर केबल को उचित क्रम में कनेक्ट करना होगा।

बैटरी को कनेक्ट करें

लाल क्लिप में से एक को अपनी कार की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ें। यह आमतौर पर पीओएस या + चिह्न के साथ आता है और निगेटिव टर्मिनल से बड़ा होता है। इसके अलावा, दूसरी लाल क्लिप को दूसरी कार के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें।

एक काली क्लिप को दूसरी कार की बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें और आखिरी काली क्लिप को अपनी कार की एक बिना रंगी हुई धातु की सतह से जोड़ दें जो बैटरी के पास न हो। आप धातु के स्ट्रट्स का उपयोग कर सकते हैं जो हुड को खुला रखते हैं।

जल्द एंट्री मारेंगी ये 2 नई कॉम्पैक्ट एसयूवी, स्कोडा और किआ लिस्ट में शामिल

भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा SUVs की मांग है। इसका फायदा उठाते हुए देश की दो पॉपुलर ऑटोमेकर Skoda और Kia दो नए मॉडल पेश करे जा रहे हैं। अगर आप अगले साल तक एक सब-4-मीटर एसयूवी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो हमारा ये आर्टिकल आपके काम आ सकता है।

Skoda Compact SUV

Skoda की Compact SUV को हाल ही में भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा था। उम्मीद है कि ये अगले साल मार्च में लॉन्च की जाएगी। स्पाई शॉट्स में एसयूवी का डिजाइन सामने आया है। इसमें उल्टे एल-आकार के एलईडी टेल लैंप, एक स्प्लिट हेडलैंप सेटअप, इंटीग्रेटेड हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ छोटा सा रूफ स्पॉइलर शामिल है। कुल मिलाकर ये कुशाक के साथ बहुत कुछ साझा करती हुई नजर आ रही है।

परिचित MQB A0 IN प्लेटफॉर्म पर आधारित, यह कॉम्पैक्ट एसयूवी 1.0-लीटर TSI इंजन द्वारा संचालित होगी, जो 115 bhp और 178 Nm का पीक टॉर्क पैदा करेगा। स्कोडा अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्प पेश करेगी।

बहुत नाजुक होता है गाड़ी का ये हिस्सा! बड़े नुकसान से बचना है, तो हमेशा ध्यान रखें ये बातें

कार को सीधी धूप में पार्क करने से विंडशील्ड पर अत्यधिक तापमान का प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से इसमें दरार आ सकती है। कांच के टिंट भी यूवी किरणों के प्रति संवेदनशील होते हैं और ये क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। विंडशील्ड वाइपर की कंडीशन कांच को कई तरह से प्रभावित कर सकती है। ऐसे में विंडशील्ड वाइपर का भी ख्याल रखना जरूरी है।

नई दिल्ली। कार की विंडशील्ड काफी उपयोगी और नाजुक हिस्सा होती है। इसकी मदद से धूल, गंदगी और बाहर से आने वाली चीजों को केबिन के अंदर प्रवेश करने से रोका जा सकता है। विंडशील्ड की देखभाल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आइए जान लेते हैं कि विंडशील्ड को सुरक्षित रखने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।

सीधी धूप में गाड़ी न पार्क करें

कार को सीधी धूप में पार्क करने से विंडशील्ड पर अत्यधिक तापमान का प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से इसमें दरार आ सकती है। कांच के टिंट भी यूवी किरणों के प्रति संवेदनशील होते हैं और ये क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। गैरेज, बेसमेंट या किसी अन्य छायादार स्थान पर पार्किंग करने से कांच को टूटने से बचाया जा सकता है।

चिप्स और क्रैक्स का ध्यान रखें

जब कोई बाहरी वस्तु विंडशील्ड से टकराती है, तो इसकी वजह से कांच पर चिप्स या क्रैक पड़ सकती हैं। कांच पर इस तरह के बुलबुले बनने से चाहे उसका आकार कुछ भी हो अगर मरम्मत न की गई तो विंडशील्ड को काफी नुकसान हो सकता है। ऐसे में कांच का विशेष ध्यान रखें। समय रहते मरम्मत कराने से बड़ा नुकसान टाला जा सकता है।

विंडशील्ड वाइपर बदलते रहें

विंडशील्ड वाइपर की कंडीशन कांच को कई तरह से प्रभावित कर सकती है। ऐसे में विंडशील्ड वाइपर का भी ख्याल रखना जरूरी है। वाइपर मुख्य रूप से दो कंपोनेंट से बना होता है, अंदर की तरफ मेटल स्ट्रक्चर और उसके ऊपर रबर कोटिंग होती है। अगर विंडशील्ड वाइपर की रबर घिस जाए, तो इसे बदलना सुनिश्चित करें।

घर में घुसकर मारने के बयान पर चुप्पी क्यों

योगेंद्र योगी

दरअसल अमरीका भी खाड़ी देशों की तरह भारत से रिश्ते और प्रगाढ़ करने की दिशा में बढ़ रहा है। मुद्दा चाहे सैन्य साजो-सामान की सप्लाई का हो या फिर चीन के खिलाफ दमदार सहयोगी का हो, अमरीका को अंदाजा है कि चीन का मुकाबला भारत ही कर सकता है'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के घर में घुस कर मारने के बयान के बाद भी पूरी दुनिया चुप रही। पाकिस्तान के सिवाय विश्व के किसी भी देश ने इस पर कोई सख्त टिप्पणी करना तो दूर, सामान्य प्रतिक्रिया तक नहीं जताई। विश्व के देशों की समझ में आ गया है कि आतंकवाद के लिए बदनाम पाकिस्तान जैसे देश के लिए भारत से रिश्ते बिगाडऩा समझदारी नहीं है। बदले हुए वैश्विक परिदृश्य में हर देश सिर्फ नेशन फस्ट की नीति पर चल रहा है। इसलिए कोई देश किसी दूसरे देश के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया तब तक नहीं देता है, जब तक कि उसके हितों पर आंच नहीं आए। ब्रिटिश अखबार गार्डियन की रिपोर्ट के बाद ठीक ऐसा ही हुआ है। गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में हुई करीब 20 हत्याएं संयुक्त अरब अमीरात से संचालित भारतीय खुफिया एजेंसियों के स्लीपर सेल के जरिए अंजाम दिए गए। हत्याओं को अंजाम देने के लिए स्थानीय अपराधियों या गरीब पाकिस्तानियों को लाखों रुपए देने का आरोप है। भारतीय एजेंटों ने हत्याओं को अंजाम देने के लिए कथित तौर पर जिहादियों को भी भर्ती किया, उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि वे काफिरों को मार रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2019 के पुलवामा हमले के बाद से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ द्वारा करीब 20 इस तरह की हत्याएं की गईं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पाकिस्तान द्वारा दिए गए सबूतों और सीमा के दोनों ओर के खुफिया अधिकारियों के इंटरव्यू पर आधारित है। इस खबर के बाद भी पाकिस्तान को छोड़ कर दुनिया के सभी देश खामोश रहे। भारत ने भी मौजूदा दौर में बदली हुई विदेश नीति के तहत इस बात को दबाने या छिपाने के बजाय विश्व के समक्ष साफ जाहिर कर दिया कि आतंकी कार्रवाईयों पर भारत चुप नहीं बैठेगा, बल्कि ऐसी कार्रवाईयों का मुंहतोड़ जवाब देगा। हालांकि भारत ने गार्डियन की इस रिपोर्ट का न तो खंडन किया और न ही समर्थन किया। भारत ने विश्व के सामने अपनी नीति को स्पष्ट कर दिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने पूर्व में दिए गए बयान से भी एक कदम आगे निकल गए। सिंह ने पाकिस्तान को उसकी धरती पर आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए सहायता की पेशकश कर डाली। उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान खुद को अक्षम महसूस करता है तो भारत आतंकवाद को रोकने के लिए सहयोग करने को तैयार है। हालांकि, उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी कि अगर उसका मकसद आतंकवाद का इस्तेमाल कर भारत को अस्थिर करना है तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। यह सख्त टिप्पणी उनके द्वारा पाकिस्तान को चेतावनी देने के एक हफ्ते बाद आई है कि भारत सीमा पार करके भागने की कोशिश करने वाले किसी भी आतंकवादी का पीछा करेगा। उन्होंने कहा था कि अगर वे पाकिस्तान भागेंगे तो हम उन्हें मारने के लिए पाकिस्तान में घुसेंगे। जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का बिना नाम लिए कहते हैं कि छोटे-छोटे देश जो आज आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। आज का भारत घर में घुस कर मारता है। पाकिस्तान ने राजनाथ सिंह के इस बयान को भडक़ाऊ बताते हुए इसकी निंदा की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का इतिहास खुद की रक्षा करने के लिए गवाही देता है। पाकिस्तान ने कहा कि हमने हमेशा क्षेत्र में शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है और यह भी कहा कि इतिहास पाकिस्तान के दृढ़ संकल्प और खुद की रक्षा करने की क्षमता की गवाही देता है। यह पहला मौका है जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक कदम आगे बढ़ते हुए परिवर्तित नीति का खुलासा किया है। इससे पहले ऐसे मामलों से भारत कन्नी काटता रहा है। आतंकियों के लगातार मारे जाने पर पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया था। पाकिस्तान ने दावा किया था कि इस कार्रवाई को अंजाम देने वाले एक भारतीय पासपोर्ट धारक को गिरफ्तार किया गया है। भारत ने तब इसे बेबुनियाद बताया था। इसी तरह कनाडा में आतंकी निज्जर की हत्या और अमरीका में आतंकी पन्नू की हत्या के प्रयासों के आरोपों पर भारत ने रक्षात्मक रुख अख्तियार करते हुए ऐसी कार्रवाईयों का खंडन किया था। किन्तु गार्डियन की खबर के बाद भारत ने अपना स्टैंड बदल लिया है।

इस बदली हुई नीति का संदेश विश्व को दिया गया है। गौरतलब है कि कनाडा, अमरीका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और अन्य देशों में खालिस्तानी आतंकियों ने भारत के खिलाफ धरने-प्रदर्शन और हिंसात्मक कार्रवाईयां की हैं। भारत इन पर अपना विरोध जताता रहा है। रक्षामंत्री का बयान इन देशों और इनमें पल रहे आतंकियों के लिए भी चेतावनी है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हर मामले की एक हद होती है। अब भारत किसी को बख्शेगा नहीं। विश्व के देश भारत के बदले हुए तेवर से स्तब्ध हैं। किसी भी देश ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। इसकी प्रमुख वजह है कि भारत सभी देशों से कमोबेश द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत कर रहा है। इसमें रणनीति और

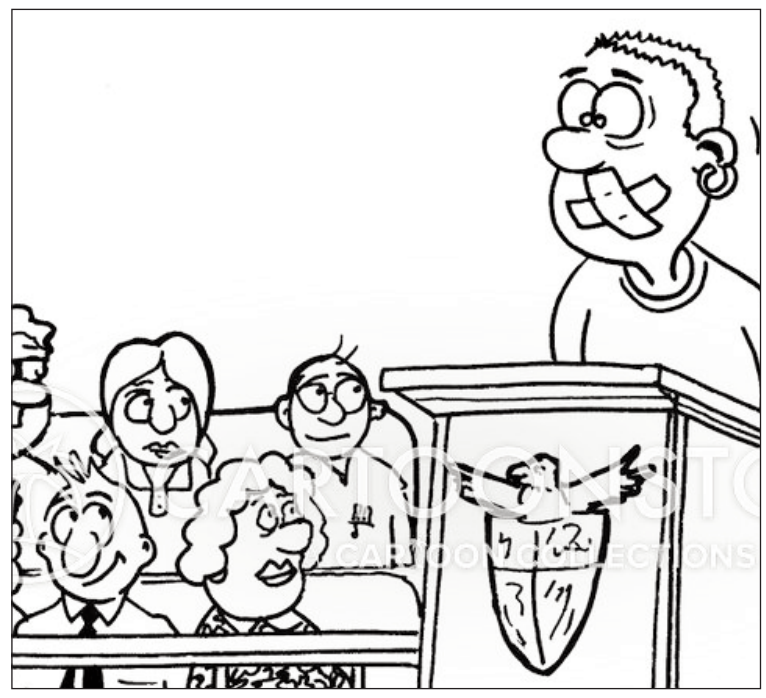

व्यापारिक संबंध शामिल हैं। सभी देशों को लगता है कि एक अरब 40 करोड़ की आबादी वाला भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। दो देशों के आपसी संबंधों के मामले में बीच में पडऩा अब कोई भी देश नहीं चाहता। सभी देशों को सिर्फ अपने हितों की फिक्र है। यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की यात्रा के दौरान जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के समक्ष भारत के कश्मीर का मुद्दा उठाया, तब उन्होंने इसे द्विपक्षीय तरीके से हल किए जाने का सुझाव देते हुए टाल दिया। पाकिस्तान कई देशों से भारत पर दबाव डलवाने का प्रयास कर चुका है, किन्तु किसी भी देश ने इसमें बीच में आने से इंकार कर दिया। गौरतलब है कि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते अब नए दौर में पहुंच गए हैं। सऊदी अरब को अंदाजा है कि कच्चे तेल पर टिकी अर्थव्यवस्था के भरोसे नहीं रहा जा सकता। तेल के स्त्रोत समाप्त होने से पहले ही सऊदी अरब सुविधासम्पन्न ऐसा देश बनना चाहता है ताकि विश्व के पर्यटन स्थल पर चमक सके। यही वजह है कि कुछ अर्से पहले तक कट्टर इस्लामिक मुल्क रहे सऊदी अरब के प्रिंस ने व्यापक बदलाव की ठान ली है। पुराने दकियानूसी तौर-तरीकों को बदल कर सऊदी अरब आधुनिक सोच के बदलाव का सबब बन रहा है।

इसी के मद्देनजर भारत और सऊदी अरब ने हाल ही में कई व्यापारिक समझौते किए हैं। भारत ने खाड़ी के देशों में रिश्तों का नया अध्याय लिखा है। अमरीका की प्रमुख मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने अपने लेटेस्ट आर्टिकल में मिडिल ईस्ट में भारत के अहम शक्ति के रूप में उभरने के बारे में लिखा है। इसे पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में सबसे दिलचस्प भू-राजनीतिक घटनाक्रम में से एक के रूप में देखा जा रहा है। इस आर्टिकल में इजराइल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित क्षेत्र के प्रमुख देशों के साथ भारत के गहरे और बढ़ते संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया है कि ये देश बदलती अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में भारत के उभार का लाभ उठाने के इच्छुक नजर आ रहे हैं। आर्टिकल के लेखक स्टीवन ए. कुक ने तर्क दिया कि इस बात की बेहद कम संभावना है कि अमरीका इस घटनाक्रम में हस्तक्षेप कर सकता है। दरअसल अमरीका भी खाड़ी देशों की तरह भारत से रिश्ते और प्रगाढ़ करने की दिशा में बढ़ रहा है। मुद्दा चाहे सैन्य साजो-सामान की सप्लाई का हो या फिर चीन के खिलाफ दमदार सहयोगी का हो, अमरीका को अंदाजा है कि चीन का विश्व में यदि कोई देश मुकाबला कर सकता है तो वह भारत है। इसी तरह यूरोपीय देश भी भारत में व्यापार की संभावनाएं तलाशते हैं। कोई भी देश पाकिस्तान का साथ देकर भारत से पंगा नहीं लेना चाहता।

संपादक की कलम से

बनाम छोटा पप्पू

मंडी संसदीय क्षेत्र ने अचानक सारे राष्ट्र की निगाहें हिमाचल की ओर मुखातिब की हैं। मानना पड़ेगा कि यह सब वहां से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत की वजह से कहीं ज्यादा हो रहा है। चुनावी फलक के दूसरे छोर पर वीरभद्र सिंह परिवार का पारंपरिक दुर्ग और उनकी राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकार खड़ा है। बात कहां से चली और कहां तक पहुंचेगी, लेकिन आरंभिक जोश से ही मालूम पड़ता है कि मंडी चुनाव में जाहिर मंतव्य किसी भी हद तक जहरीला और व्यक्तिगत आक्षेपों में माहिर होना चाहता है। यहां कंगना की पृष्ठभूमि, ग्लैमर और बेबाकी के सामने विक्रमादित्य सिंह की राजनीतिक समझ, वाकपुटता और सत्ता में भागीदारी खड़ी है। कंगना का प्रचारतंत्र देश के लिए और देश के सामने, भाजपा का अभ्यास वर्ग है, इसलिए जरूरी नहीं कि वह हिमाचली मुद्दों की बिसात तक ही रहे। इसलिए वह सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय बहस की पात्र बनी रहना चाहती है और मुकाबले के हर पहलू में मंडी के स्वाभिमान और पहाड़ की बेटी होने का मर्म जाग्रत करती है। इस तरह वह न तो अधकचरी और न ही आसान हस्ती हैं। विवाद उनका गहना और चर्चाएं उनका पोशाक है। हिमाचल के राजनीतिक इतिहास में यह दूसरी बार हो रहा है जब कोई सियासी शख्सियत अपनी गैर मौजूदगी में भी चर्चाओं से दूर नहीं। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को जब प्रदेश की राजनीति से दूर केंद्रीय मंत्री के दायित्व में सीमित करने के जोरदार प्रयास हो रहे थे, तब भी वह हिमाचल की हर बहस के प्रमुख पात्र थे। हिमाचल के प्रवेशद्वारों यानी सोलन व ऊना जिलों में वह बयान दाग कर विपक्ष को तब तक चर्चा का मौका देते थे, जब तक वह दिल्ली नहीं लौट जाते। उनकी शब्दावली से निकले रौंदू या मकड़झंडू जैसे शब्दों की व्याख्या आज भी विरोधियों के सिर में खुजली करती है, जबकि उनकी हाजिरजवाबी का अंदाज आजकल के नेताओं में ढूंढे नहीं मिलता।

ऐसे में कंगना का राजनीतिक अवतार पुनः बहस के कटोरे में कई खड्डों का पानी भर रहा है। सवाल यह है कि हिमाचल की जनता को अब इस स्तर की बहस में मजा आने लगा है। क्या वह नारी होने के कारण विरोधियों पर भारी होने जा रही है। क्या उसे राष्ट्रीय बहस में हिमाचल के मुद्दे गौण करने से लाभ होगा या कांग्रेस की लंका जलाते हुए अपने हाथ जलाने चाहिएं। जो भी हो, मनाली में उसके निशाने अगर बड़े पप्पू बनाम छोटे पप्पू को खोज रहे हैं, तो यह नई राजनीति का पहला संदेश भी है। इस दौर की आक्रामकता की पेशगी में कंगना बता चुकी है कि वह अपनी तरह की बिसात पर कुछ भी फैला सकती है। प्रदेश में वह बनाम राजनीति का उद्भव तो ढूंढ चुकी है, लिहाजा उपमाएं बदलेंगी और सरोकार भी रक्षा कवच पहनेंगे। जो भी हो हिमाचल में अब सवाल कंगना बनाम विक्रमादित्य सिंह तक ही नहीं। बागी कांग्रेसी बनाम कांग्रेस, राजनीतिक गोटियां बनाम हकीकत, दोस्त बनाम कार्यकर्ता, पूर्व मुख्यमंत्री बनाम वर्तमान, डबल इंजन बनाम व्यवस्था परिवर्तन और इसी तरह उम्मीदवारों के चयन में कहीं गद्दी बनाम चौधरी, पंडित बनाम राजपूत और दलित बनात कबायली भी होने लगा है। ऐसे में कांग्रेस क्या ओपीएस, रोजगार, निवेश, केंद्र संबंधों, हिमाचली अधिकारों, और सवा साल की सत्ता के बनाम भाजपा के खोट कुशलता से रख पाएगी। जनता के लिए बहस को पटरी पर लाने की चुनौती दोनों पार्टियों की रहेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कांग्रेस के लिए बागी विधायकों को निपटाना सबसे बड़ी चुनौती है, लिहाजा बयानों की फेहरिस्त में जाहिर तलख्यिों का विवरण ढूंढना कठिन है। हिमाचल की जनता के लिए सियासी तापमान के मायने जिस मोड़ पर ले आए हैं, वहां हम क्षेत्रवाद, जातिवाद, परिवारवाद और राजनीति के अवसरवाद को और हावी होते देख सकते हैं। हम बतौर नागरिक समाज जिसे वर्षों से खोज रहे हैं, क्या वैसा प्रतिनिधित्व इस बार मिल पाएगा। केंद्र में कंगना व विक्रमादित्य में से कोई भी पहुंचे, लेकिन हिमाचल के सवाल वहां पहुंचने चाहिएं।

चर्चा

खटाखट कैसे मिटेगी गरीबी

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'गरीबी मिटाओ' का एक फॉर्मूला दिया है। उनके मुताबिक, यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, तो प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला के बैंक खाते में एक लाख रुपए सालाना जमा कराए जाएंगे। वह गरीब परिवार किसान, मजदूर या किसी का भी हो सकता है, उस परिवार की महिला को 8500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। यह आर्थिक मदद तब तक जारी रहेगी, जब तक वह परिवार गरीबी-रेखा से बाहर नहीं आ जाता। क्या कांग्रेस ने ऐसी योजना के अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है? सबसे अहम सवाल तो गरीबों की संख्या का है। दरअसल ऐसे गरीबों की देश में कितनी संख्या है, यह न तो कांग्रेस को पता है और न ही सरकार यह डाटा साझा करना चाहती है। गरीबी-रेखा की परिभाषा तक निश्चित नहीं है। देश में गरीबी की स्थिति क्या है, उसे लेकर भी विरोधाभास हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर आर्थिक असमानता के यथार्थ को दोहराया है। देश के 22 सबसे अमीर भारतीयों के पास इतना धन है, जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। राहुल गांधी के अनुसार, मोदी सरकार ने अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। यह देश के महज 25-30 धन्नासेठों की इतनी राशि है, जितनी 24 साल तक मनरेगा के जरिए मजदूरों को दी सकती थी। राहुल यह चुनाव देश के गरीबों और 22-25 अरबपतियों के बीच की लड़ाई मानते हैं। यह वामपंथी सोच का विश्लेषण है।

यदि अरबपतियों के पास बेइंतहा आर्थिक संसाधन हैं, तो उनकी कंपनियां लाखों लोगों को रोजगार भी देती हैं और करोड़ों रुपए के कर भी अदा करती हैं। बहरहाल राहुल गांधी का दावा है कि कांग्रेस देश से खटाखट गरीबी को मिटा देना चाहती है। हमारी जो गारंटी है, उसके जरिए हम एक ही झटके में गरीबी समाप्त कर देना चाहते हैं। राहुल गांधी की दादी एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी 1971 में 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था और प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीता था। उसके बाद की कांग्रेस सरकारों में भी 'गरीबी' एक बुनियादी एजेंडा रहा, लेकिन एक समय आया था, जब 'योजना आयोग' (अब नीति आयोग) भी मानता था कि करीब 30 करोड़ भारतीय गरीबी-रेखा के नीचे जीने को अभिशप्त हैं। समितियां बनाई गईं, फॉर्मूले तय किए गए, लेकिन सही डाटा देश के सामने पेश नहीं किया जा सका। चूंकि अब प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक मंचों पर बार-बार दोहरा रहे हैं कि उनकी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को 'गरीबी' से बाहर निकाला है। यानी प्रधानमंत्री भी स्वीकार करते हैं कि देश में 25 करोड़ गरीब रहे हैं, जिन्हें उस रेखा से उबारा गया है। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान ही देश के सामने है, अलबत्ता कोई बिंदुवार और क्षेत्रवार आंकड़े देश के सामने नहीं रखे गए हैं। इसी दौर में आरएसएस के सरकार्यवाह (महासचिव) दत्तात्रेय होसबले ने एक आर्थिक आकलन सार्वजनिक किया था। उसके मुताबिक, देश में 23 करोड़ से अधिक भारतीय ऐसे हैं, जो 375 रुपए रोजाना की कमाई करने में भी असमर्थ हैं। वे भी गरीबी-रेखा के नीचे की आबादी हैं। सवाल है कि देश में कितने लोग गरीब हैं, जिन्हें आर्थिक मदद देकर उबारने की जरूरत है? प्रधानमंत्री मोदी देश में 81 करोड़ से अधिक लोगों को 'मुफ्त अनाज' बांट रहे हैं। जिन्हें हर माह 5 किलो अनाज की दरकार है और अभी यह योजना 5 और साल चलेगी, तो ऐसे लोग गरीब नहीं हैं, तो उन्हें किस वर्ग में रखा जाएगा? मुफ्तखोरी की कई योजनाएं हैं और नकदी भी बांटी जा रही है। ऐसा लगता है मानो 90 फीसदी भारत गरीब है। सिर्फ धन्नासेठ और उनके सम्पन्न सलाहकार ही 'अमीर' हैं। मोदी को ही सरकार के संबद्ध विभाग को आदेश देने चाहिए कि वह गरीबी की परिभाषा स्पष्ट करे, यह अहम मानवीय सरोकार है।

रमेश धवाला

आवारा-जंगली जानवर मचा रहे तबाही

अगर हम गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इस समस्या के लिए मानव का स्वार्थ जिम्मेदार है। जब तक गाय दूध देती है, या बैल हल जोतता है, हम उनको अपने घर में रखते हैं, बूढ़े होने पर आवारा छोड़ देते हैं'...

हिमाचल प्रदेश की हलचल भरी सडक़ों, शहर के शोरगुल और ग्रामीण क्षेत्रों के शांत वातावरण में एक बात कॉमन है- आवारा जानवर और जंगली जानवरों का डर। ये आवारा भटकते जीव, जिन्हें अक्सर लोगों द्वारा खुली सडक़ों या जंगलों में अपनी स्वार्थ सिद्धि होते ही घर से दूर खदेड़ दिया जाता है, मानव के लिए कई खतरे पैदा करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख खतरा कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसी तरह विकास कार्यों के कारण निरतंर जंगलों की कटाई के कारण जंगली जानवरों के निवास स्थानों पर सेंध लगाई जा रही है जिस कारण जंगलों से बाहर भोजन की तलाश और निवास स्थानों की तलाश में जंगली जानवर शहरों या गांव-घरों तक पहुंच रहे हैं। इस कारण ग्रामीण लोगों और शहरी लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें एक मुख्य समस्या है कृषि, फसलों में इनकी दखल। पिछले हफ्ते मैं ज्वालामुखी विधानसभा के एक छोटे से गांव मजीन में गया हुआ था। वहां रास्ते में कुछ लोग मिले जो कुछ आवारा पशुओं को सडक़ पर खदेड़ रहे थे। मैंने ये सब देख कर अपनी गाड़ी रोक कर ग्रामीणों से बात की तो पता चला कि कोई रात के अंधेरे में इन पशुओं को गाड़ी में छोड़ कर चला गया है। ग्रामीण परेशान थे क्योंकि अभी गेहूं पकने का समय है और इन आवारा जानवरों ने उनके खेतों में आतंक मचाया हुआ है।

कृषि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, जो कि आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करती है और जीविका के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करती है। हिमाचल में आज भी कृषि के लिए गाय-बैल सहित अन्य कई जानवर भिन्न-भिन्न रूपों से सहायक है, किन्तु आज गाय, बैल, जंगली सूअर, हिरन और बंदरों सहित कई आवारा जानवर किसानों की आजीविका और कृषि भूमि की उत्पादकता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। ज्वालामुखी और देहरा विधानसभा क्षेत्रों के यही हाल हैं। हिमाचल प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और अधिकांश लोग किसान और बागवान हैं। आप चाहे ऊना के समतल में जाओ या शिमला और किन्नौर के पहाड़ों में, किसान आवारा और जंगली जानवरों से फसलों को हुए नुक्सान के कारण खेतीबाड़ी छोडऩे को विवश हैं। हालांकि यह समस्या केवल हिमाचल की ही नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष की समस्या है। देश के अन्य राज्यों में चाहे किसान इस समस्या के प्रति इतने मुखर न हों, लेकिन हिमाचल में किसान फलों और फसलों को हो रहे नुक्सान पर कई बार आन्दोलन एवं विधानसभा का घेराव कर चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार ये जानवर हर साल करीब 500 करोड़ की फसलों का नुक्सान हिमाचल प्रदेश में करते हैं। हिमाचल के कई स्थानों पर किसानों ने फसल बीजना ही बंद कर दी है। मेरे ज्वालामुखी विधानसभा के कई क्षेत्र जैसे भडोली, कुटियारा आदि उपजाऊ क्षेत्रों में लोगों ने जंगली और आवारा जानवरों के कारण खेतीबाड़ी करना छोड़ दिया है, जो कि प्रदेश हित में एक सोचनीय विषय है। केन्द्र सरकार ने सन-1972 में बंदरों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया था, जो कि अब प्रदेश की हालत देखते हुए हटना चाहिए। राज्य सरकार के आग्रह पर हिमाचल की कई पंचायतों में बंदरों को वर्मिन (हिंसक जानवर) घोषित किया है एवं फल व फसलों को नुक्सान देने वाले बंदरों को मारने की अनुमति केंद्र से मिली हुई है। लेकिन इस सबके बावजूद राज्य सरकार ने बंदरों को मारने से हाथ खींच लिए हैं। सरकार चाहती है कि किसान खुद बंदरों को मारें, लेकिन हाथों में हल पकडने वाले किसान बंदूक कैसे पकड़ें? एक सर्वे के अनुसार प्रदेश में पौने चार लाख के करीब बंदर हैं, जो कि पिछले दो दशकों से फसलों को नुक्सान पहुंचा रहे हैं।

हिमाचल के किसान यह मांग करते आए हैं कि बंदरों के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा है, उसको हटाया जाए। पहले भारत विदेशों में प्रतिवर्ष करीब 60 हजार बंदरों को निर्यात करता था, जिस पर पशु प्रेमी संगठनों के विरोध के कारण प्रतिबन्ध लगाया गया है। हिमाचल सरकार ने पांच साल पहले यह प्रयास भी किया कि बंदरों को नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर आदि राज्यों में भेजा जाए, किन्तु सरकार का यह प्रयास भी किन्हीं कारणों से सफल नहीं हो सका। बंदरों, सूअरों और हिरणों के साथ-साथ आवारा पशुओं की समस्या भी काफी चिंतनीय

है। यह पशु फसलों को तो नुक्सान पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ कई बार रोड एक्सीडेंट्स का कारण भी बनते हैं। हिमाचल उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद हजारों गायें और बैल राज्य भर में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर घूमते रहते हैं, जो मोटर चालकों के लिए मुख्य रूप से एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। एक सर्वे के अनुसार हिमाचल में प्रतिदिन एक एक्सीडेंट आवारा पशुओं के कारण होता है। मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र ज्वालामुखी में जहां हजारों लोग माथा टेकने मंदिर आते हैं, उनको पशुओं के जमावड़े के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार ये पशु बीच सडक़ पर खड़े होकर ट्रैफिक जाम, तो कभी एक्सीडेंट्स का कारण बनते हैं। अपने कार्यकाल में मैंने इस समस्या से निपटने के लिए विधानसभा में कई गौशालाओं का निर्माण करवाया, जिससे आवारा पशुओं की संख्या में कुछ कमी हुई। अगर हम गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इस समस्या के लिए मानव का स्वार्थ जिम्मेदार है। जब तक गाय दूध देती है, या बैल हल जोतता है, हम उनको अपने घर में रखते हैं, जैसे ही मनुष्य की स्वार्थ सिद्धि पूर्ण हो जाती है तो इन्हें आवारा छोड़ दिया जाता है।

इसी तरह जंगलों की निरंतर कटाई के कारण, जंगलों को उखाड़ कई विकास कार्यों को धरातल पर लाने के कारण मनुष्य द्वारा जंगली जानवरों, जैसे कि बंदरों, हिरणों या जंगली सूअरों के निवास स्थानों को खत्म किया जा रहा है तथा साथ ही साथ इनके भोजन के मुख्य स्त्रोत जल-जंगल से इन्हें दूर किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि ये जानवर भोजन की तलाश और सुरक्षित निवास स्थान की तलाश में शहरों या गांवों की ओर रुख करेंगे। सरकार को ज्यादा से ज्यादा नीड बेसिस पर सेंचुरी, पार्क और गौशाला का निर्माण करना चाहिए। अवैध वन कटान पर प्रतिबंध तथा इनके निवास स्थानों में कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। कई अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं।

छिलकों की छाबड़ी : हाई लेवल मीटिंग जारी है!

महंगाई का मसला चूंकि सरकार के गले की फांस बना था, इसलिए सरकार ने महंगाई रोकने के लिए एक हाईपावर कमेटी बना दी। अब सरकार तो कमेटी बनाकर निश्चिंत हो गई, लेकिन कमेटी को समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए? चूंकि गले में बंधा ढोल बजाना ही था, लिहाजा कमेटी ने हाई लेवल पर यह डिसाइड किया कि क्यों न महंगाई पर एक मीटिंग कर ली जाए। हाईपावर कमेटी के सदस्य चूंकि काफी हाई लेवल के लीडर थे, लिहाजा उनके प्रोटोकॉल और अन्य सुख-सुविधाओं को टॉप प्रिफरेंस देते हुए ब्यूरोक्रेसी ने राजधानी के एक टॉपमटाप होटल की टॉप मंजिल पर बने कक्ष में महंगाई पर मीटिंग रखवा दी। इस मीटिंग की भनक ज्यों ही चैनल वालों को लगी, वे बाकी काम-धाम छोडक़र उस होटल के बाहर आ जमे। ब्रेकिंग न्यूज के जरिए मुल्क की पब्लिक को यह बताया जाने लगा कि महंगाई पर मीटिंग शुरू हो चुकी है। पब्लिक खुश होकर अगली ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार करने लगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज थी, 'हाईपावर कमेटी के सदस्य विदेशी गाडियों में बैठकर मीटिंग में भाग लेने आए हैं।' पब्लिक फिर खुश हो गई कि मीटिंग जरूर बहुत महत्वपूर्ण होगी, तभी तो हाईपावर कमेटी के सदस्यों को महंगी विदेशी गाडियों में आना पड़ा, वरना वे देसी गाडियों में भी तो आ सकते थे। फिर काफी देर तक चैनलों पर उन गाडियों की तस्वीरें दिखाई जाती रहीं और पब्लिक यह अनुमान लगाती रही कि सरकार ने ये गाडियां कितनी संख्या में और कितने पैसों की खरीदी होंगी? उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज के जरिए यह बताया जाने लगा कि मुल्क में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जिस होटल में हाईपावर कमेटी की मीटिंग चल रही है, वहां चाय का एक कप तीन सौ रुपए में और विदेशी ब्रांड की व्हिस्की का एक पैग तीन हजार रुपए में मिलता है। चैनल देख रही महंगाई से त्रस्त पब्लिक अपनी पीड़ा भूलकर उन लोगों पर तरस खाने लगी जिन्हें इस होटल में आकर चाय और विदेशी शराब के इतने ज्यादा दाम चुकाने पड़ते हैं।

पब्लिक अभी तरस खा ही रही थी कि चैनलों पर अगली ब्रेकिंग न्यूज यह आई कि, 'महंगाई पर हो रही मीटिंग पूरे यौवन पर पहुंच चुकी है।' पब्लिक सांस थामे यह जानने को बेचैन हो गई कि मीटिंग में आखिर हो क्या रहा है? अब मीटिंग में क्या-क्या फैसले लिए जा रहे थे, उन पर आप भी मुलाहिजा फरमाइए। मीटिंग में हाई पावर कमेटी ने पहला फैसला यह लिया कि महंगाई पर कोई फैसला लेने से पहले दुनिया के तमाम देशों का भ्रमण करके यह पता लगाया जाए कि किस मुल्क में दालों, खाद्य पदार्थों, सरिए, सीमेंट और बजरी के क्या रेट चल रहे हैं? साथ ही यह भी पता लगाया जाए कि खाद्य पदार्थों की जमाखोरी किस-किस मुल्क में होती है और किस-किस मुल्क में नहीं होती? यह भी पता लगाया जाए कि रोटी, चावल व दालों से सस्ती ऐसी कौनसी आइटम हैं, जिन्हें खाकर पेट भरा जा सकता है?

बैठक में यह भी पता लगाने का फैसला लिया गया कि क्या 'योग' करने से भूख पर काबू पाया जा सकता है? एक सुझाव यह भी था कि क्यों न मुल्क में संतों और महात्माओं की एक हाई लेवल कमेटी बना दी जाए जो मुल्क की पब्लिक को सप्ताह में कम से कम दो दिन व्रत रखने की प्रेरणा दे और यह बताए कि व्रत रखने से आत्मा निर्मल रहती है और आत्मा निर्मल रहने से महंगाई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहरहाल मीटिंग जारी थी।

-गुरमीत बेदी

म्यांमार दालें आयात करने वाले व्यापारियों के लिए आसान होगा पेमेंट सिस्टम

परिवहन विशेष न्यूज

म्यांमार से दाल आयात करने वाले व्यापारियों के लिए भुगतान प्रणाली को आसान और सरल बनाया गया है। मंत्रालय ने बताया कि आयातकों को पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (एसआरवीए) का उपयोग करके रुपया/क्याट प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली का उपयोग करने के लिए कहा गया है। देश म्यांमार से तुअर और उड़द दाल का आयात करता है।

नई दिल्ली। सरकार ने शनिवार को कहा कि म्यांमार से दाल आयात करने वाले व्यापारियों के लिए भुगतान प्रणाली को आसान और सरल बनाया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आयातकों को पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (एसआरवीए) का उपयोग करके रुपया/क्याट प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली का उपयोग करने के लिए कहा गया है।

भारत घरेलू कमी को पूरा करने के लिए दालों के आयात पर निर्भर है। देश म्यांमार से तुअर और उड़द दाल का आयात करता है। इसमें कहा गया है कि उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने म्यांमार से दालों के आयात से संबंधित यांगून में भारतीय मिशन के साथ संशोधित विनिमय दरों और म्यांमार में आयातकों द्वारा रखे गए स्टॉक के मद्देनजर आयात कीमतों जैसे मुद्दों पर चर्चा की।

व्यापार लेनदेन को सरल बनाने की तैयारी

मंत्रालय ने कहा कि भारतीय मिशन ने सचिव को सूचित किया कि व्यापार लेनदेन को सरल बनाने और उन्हें अधिक कुशल बनाने के लिए इस साल 25 जनवरी से रुपया/क्यात निपटान सिस्टम चालू कर दिया गया है।

सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार ने 26 जनवरी, 2024 को एसआरवीए के तहत भुगतान प्रक्रियाओं के लिए गाइडलाइन जारी किए।

भारतीय मिशन ने सचिव को यह भी बताया कि नया तंत्र समुद्र और सीमा व्यापार दोनों और वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं के व्यापार के लिए भी लागू होगा।

मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि व्यापारियों द्वारा इस तंत्र को अपनाने से मुद्रा रूपांतरण से जुड़ी लागत कम हो जाएगी और कई मुद्रा वार्तालापों की आवश्यकता को समाप्त करके विनिमय दरों से संबंधित जटिलताएं खत्म हो जाएंगी।

इसमें कहा गया है कि व्यापारिक समुदायों, विशेष रूप से दाल आयातकों के बीच इस तंत्र के संचालन के बारे में प्रचार-प्रसार अलग से किया जा रहा है, जिसमें उनसे पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से एसआरवीए का उपयोग करके रुपया/क्याट प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली का उपयोग करने का अनुरोध किया जा रहा है।

स्टॉक की ईमानदारी से घोषणा

इस बीच, सरकार ने आयातकों और अन्य उद्योग के खिलाड़ियों जैसे मिल मालिकों, स्टॉकिस्टों, खुदरा विक्रेताओं आदि को 15 अप्रैल से पोर्टल https://fcainfoweb.nic.in/psp/ पर साप्ताहिक आधार पर आयातित पीली मटर सहित दालों के अपने स्टॉक की ईमानदारी से घोषणा करने को कहा है।

मंत्रालय ने यह भी चेतावनी दी है कि दालों के वायदा व्यापार में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति से आवश्यक वस्तु अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्टॉकहोल्डिंग संस्थाओं द्वारा साप्ताहिक स्टॉक प्रकटीकरण लागू करने और उनके द्वारा घोषित स्टॉक को सत्यापित करने के लिए भी कहा गया है।

बयान में कहा गया है कि प्रमुख बंदरगाहों और दाल उद्योग केंद्रों में स्थित गोदामों में स्टॉक को समय-समय पर सत्यापित किया जाना चाहिए और स्टॉक प्रकटीकरण पोर्टल पर गलत जानकारी देने वाली स्टॉकहोल्डिंग संस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

इसमें कहा गया है कि उद्योग जगत से फीडबैक और विभिन्न बाजार खिलाड़ियों के पास स्टॉक की स्थिति से संबंधित बाजार खुफिया जानकारी को आगे के सत्यापन के लिए एकत्र किया गया है।

ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर अब हेल्थ ड्रिंक्स के रूप में नहीं बिकेगा बॉर्नविटा या प्रोटिनेक्स

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करने वाला भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की सलाह पर वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने ई-कामर्स कंपनियों को यह निर्देश जारी किया है। साफ तौर पर कहा गया है कि सभी ई-कामर्स कंपनियां बॉर्नविटा समेत अन्य ड्रिंक्स को हेल्थ ड्रिंक्स की श्रेणी से बाहर कर लें।

नई दिल्ली। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कामर्स प्लेटफार्म से किसी भी पेय पदार्थ व बेवरेज को हेल्थ ड्रिंक के रूप में नहीं बेचने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करने वाला भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की सलाह पर वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने ई-कामर्स कंपनियों को यह निर्देश जारी किया है।

हेल्थ ड्रिंक्स की कैटेगरी से होंगे बाहर

मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है कि बॉर्नविटा समेत कई ड्रिंक्स व बेवरेज हेल्थ ड्रिंक्स की श्रेणी में बेची जा रहे है जबकि एफएसएसएआई एक्ट के तहत हेल्थ ड्रिंक्स का कोई प्रावधान ही नहीं है। साफ तौर पर कहा गया है कि सभी ई-कामर्स कंपनियां बॉर्नविटा समेत अन्य ड्रिंक्स को हेल्थ ड्रिंक्स की श्रेणी से बाहर कर लें।

मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक जारी निर्देश में बॉर्नविटा का नाम उदाहरण के तौर पर लिया गया है। यह निर्देश सभी ड्रिंक्स व बेवरेज के लिए लागू होगा जिनकी बिक्री हेल्थ ड्रिंक्स के रूप में हो रही है। ई-कामर्स साइट पर बॉर्नविटा के साथ प्रोटिनेक्स, हार्लिक्स जैसे कई उत्पाद हेल्थ ड्रिंक्स के रूप में बेचे जा रहे हैं।

इस साल गर्मी में नहीं होगी पावर कट की परेशानी! ये है सरकार का मास्टर प्लान

मौसम विभाग का अनुमान है कि गर्मियों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। भीषण गर्मी की वजह से बिजली की डिमांड में तेज उछाल आ सकता है और उससे पावर कट की समस्या भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में बिजली मंत्रालय पावर सप्लाई को दुरुस्त रखने का खास प्लान बना रहा है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। हर साल गर्मी आते ही बिजली की डिमांड बढ़ जाती है। कई बार डिमांड के मुताबिक सप्लाई ना होने से पावर कट की समस्या हो जाती है। इससे लोग गर्मी में झुलसने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन, इस बार सरकार ने गर्मी के लंबे सीजन को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी की है।

कितनी बिजली की रहेगी डिमांड?

बिजली मंत्रालय ने इस गर्मी यानी अप्रैल से जून के दौरान बिजली की मांग अधिकतम 260 गीगावॉट रहने का अंदाजा लगाया है।

हालांकि, पिछले साल सितंबर में बिजली की अधिकतम मांग 243 गीगावॉट के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, जो मंत्रालय के अनुमान से कहीं अधिक थी।

क्या है सरकार का प्लान

केंद्र सरकार ने गर्मी का सीजन लंबा खिंचने की संभावना को देखते हुए गैस से बिजली उत्पादन करने वाले सभी स्टेशनों को 1 मई से 30 जून तक अपना प्लांट चालू रखने का निर्देश दिया है। अभी गैस-बेस्ड जेनरेटिंग स्टेशंस (GBS) के एक बड़ा हिस्से का इस्तेमाल नहीं हो पाता। वजह मुख्य तौर पर कमर्शियल है।

हालांकि, केंद्र सरकार का मानना है कि इन स्टेशनों का इस्तेमाल करने से गर्मियों में पावर सप्लाई को दुरुस्त रखने में मदद मिलेगी।

इसके तहत ग्रिड-इंडिया पहले से GBS को बता देगा कि कितने दिनों के लिए गैस वाली बिजली की जरूरत है।

लेकिन, जिन GBS ने डिस्ट्रिब्यूटिंग लाइसेंसहोल्डर्स के साथ पावर परचेजिंग एग्रीमेंट कर रखा है, वे पहले उन्हीं को बिजली सप्लाई करेंगे। अगर उस बिजली का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो उसे पावर मार्केट में पेश किया जाएगा।

और क्या उपाय कर रही सरकार?

मौसम विभाग (IMD) ने 2024 की गर्मियों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की अनुमान लगाया है। ऐसे में बिजली मंत्रालय पावर सप्लाई को दुरुस्त रखने के दूसरे विकल्पों पर भी गौर कर रहा है।

इनमें मानसून के दौरान पावर प्लांट का समुचित रखरखाव और नई क्षमता में तेजी से वृद्धि जैसी चीजें शामिल है।

'बॉर्नविटा' पर सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को दी हिदायत, कहा- हेल्थ ड्रिंक्स कैटेगरी से हटाएं

परिवहन विशेष न्यूज

एनसीपीसीआर की ओर से की गई जांच के बाद एक परामर्श जारी करते हुए बताया गया है कि बोर्नविटा में चीनी का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक होता है। ऐसे में इसे हेल्थ ड्रिंक्स कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को एडवाइजरी जारी कर उन्हें अपने पोर्टल और प्लेटफॉर्म्स पर बोर्नविटा समेत सभी ड्रिंक्स और बेवरेज को 'हेल्थ ड्रिंक्स' की श्रेणी से हटाने का निर्देश दिया है। 10 अप्रैल को जारी अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा, ₹राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सीआरपीसी अधिनियम 2005 की धारा 14 के तहत अपनी जांच के बाद निष्कर्ष निकाला है कि देश में खाद्य कानूनों के तहत कोई भी ड्रिंक 'स्वास्थ्य पेय' या हेल्थ ड्रिंक्स के रूप में परिभाषित नहीं है।

एनसीपीसीआर की ओर से की गई जांच के बाद यह बात सामने आई है बोर्नविटा में चीनी का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक होता है। इससे पहले, एनसीपीसीआर ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की अपील की थी जो सुरक्षा मानकों और दिशानिर्देशों को पूरा करने में विफल रहे हैं। कुछ कंपनियों पर आरोप है कि वे पावर सप्लिमेंट्स को 'स्वास्थ्य पेय' के रूप में पेश कर रहे हैं। नियामक के अनुसार, देश के खाद्य कानूनों में 'स्वास्थ्य पेय' (हेल्थ ड्रिंक्स) को परिभाषित नहीं किया गया है और इस नाम पर कुछ भी बेचना नियमों का उल्लंघन है। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में, एफएसएसएआई ने भी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को डेयरी-आधारित या माल्ट-आधारित पेय पदार्थों को 'स्वास्थ्य पेय' के रूप में लेबल नहीं करने का निर्देश दिया था। पिछले साल, शीर्ष बाल अधिकार निकाय एनसीपीसीआर ने मोंडेलेज इंडिया के स्वामित्व वाली ब्रांड बोर्नविटा को सभी श्भ्रामकश् विज्ञापनों, पैकेजिंग और लेबल को वापस लेने का निर्देश दिया था। एक वीडियो में दावा किया गया था कि इसमें चीनी की मात्रा सामान्य से अधिक है।

मोदी सरकार में म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट ने दिया बंपर रिटर्न, अब यूपी-बिहार से आ रहे सबसे ज्यादा निवेशक

परिवहन विशेष न्यूज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली बीजेपी सरकार 2014 में सत्ता में आई। उसके बाद से इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड्स ने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है। इन दोनों ने सालाना औसतन 14 प्रतिशत मुनाफा दिया है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर रजिस्टर्ड होने वाले नए निवेशकों में से अधिकतर यूपी बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से हैं।

नई दिल्ली। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद इक्विटी मार्केट में हर साल औसतन करीब 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। म्यूचुअल फंड निवेशकों को भी इस अवधि के दौरान हर साला औसतन 14 प्रतिशत रिटर्न मिला है। इन 10 वर्षों के दौरान म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) में छह गुना से ज्यादा की वृद्धि रही है।

इंडस्ट्री का AUM 31 मार्च 2014 के 8.25 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2024 को 53.40 लाख करोड़ रुपये हो गया है। 4.21 करोड़ निवेशक आधार के साथ म्यूचुअल फंड उद्योग के एयूएम ने हाल में 55 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है। बीते 10 वर्षों में कुल खातों की संख्या भी 3.8 करोड़ से बढ़कर इस वर्ष 31 मार्च तक 17.79 करोड़ हो गई है।

बीते 10 वर्षों के दौरान पांच लार्ज-कैप म्यूचुअल फंड योजनाओं ने निवेशकों को हर साल औसतन 14.7 से 18.17 प्रतिशत रिटर्न दिया है। शीर्ष पांच मिड-कैप फंड्स ने औसतन 20.2 से 21 प्रतिशत रिटर्न दिया है। शीर्ष पांच लार्ज एंड मिडकैप फंड्स ने हर वर्ष औसतन 16.8 से 22.34 प्रतिशत रिटर्न दिया है। शीर्ष पांच स्माल-कैप फंड्स ने भी इस अवधि के दौरान 18.74 प्रतिशत से 28 प्रतिशत तक रिटर्न दिया है।

ELSS में 24 प्रतिशत तक रिटर्न

2014 से 2024 के दौरान टैक्स बचत योजना इक्विटी-लिंक्ड बचत योजना (ELSS) ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। बीते 10 वर्षों में शीर्ष पांच ELSS योजनाओं ने 16.9 से 24.7 प्रतिशत तक औसत वार्षिक रिटर्न दिया है। साथ ही इन योजनाओं से निवेशकों को आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट का भी लाभ मिला है।

2014 से अब तक सोने ने कुल 97 प्रतिशत रिटर्न दिया है और इसका वार्षिक औसत रिटर्न 7.2 प्रतिशत रहा है। निफ्टी का कुल रिटर्न 262 प्रतिशत जबकि हर वर्ष का औसत रिटर्न 13.4 प्रतिशत रहा है। सेंसेक्स ने बीते 10 वर्षों में कुल 255 प्रतिशत रिटर्न दिया है और इसका हर वर्ष का औसत रिटर्न 12.6 प्रतिशत रहा है।

अपनी आंख के तारे का भविष्य सुरक्षित करना है? इन पांच बातों पर करें अमल

परिवहन विशेष न्यूज

बच्चे के जन्म लेने के बाद माता-पिता के भीतर अलग किस्म की जिम्मेदारी का अहसास होता है। लेकिन अधिकतर मामलों में पैरेंट बस बच्चे की तात्कालिक जरूरतों पर ही ध्यान देते हैं। जैसे कि उसकी सेहत का ध्यान रखना उसकी जरूरत का सभी सामान खरीदना। लेकिन अगर आप बच्चे के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपको बच्चे के जन्म के साथ ही प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए।

नई दिल्ली: बच्चे की किलकारी पूरे परिवार के लिए खुशी का एक अलग ही अहसास लाती है। हम बच्चे के जन्म लेते ही उसकी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने में जुट जाते हैं। जैसे कि उसकी सेहत का ख्याल रखना, उसके लिए कपड़े खरीदना। यहां तक कि हम उसका नाम भी बहुत सोचविचार कर रखते हैं।

लेकिन, इन चीजों के साथ हमें बच्चे के वित्तीय भविष्य पर खास ध्यान देना चाहिए। हम पांच उपाय बता रहे हैं, जिनसे आप अपनी आंख के तारे का आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं।

बच्चे की पढ़ाई की बनाए योजना

शिक्षा किसी भी इंसान को बेहतर बनाने का पहला पड़ाव है। आज चीन जैसे देशों में पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि बहुत से कपल बच्चा पैदा करने से ही परहेज करने लगे हैं। यही वजह है कि आपको बच्चे की बचत योजना में निवेश करना चाहिए।

सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाना

अगर आपके घर में बेटी की किलकारी गूंजी है, तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलना निवेश का सबसे शानदार विकल्प हो सकता है। इसमें 8.2 प्रतिशत का शानदार ब्याज मिलता है। आप इसमें लगातार निवेश करके बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए पैसे जमा कर सकते हैं।

लाइफ इंश्योरेंस खरीदना जरूरी

बतौर पैरेंट यह तय करना आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो आपके बच्चे का आर्थिक भविष्य सुरक्षित रहे। उसकी परवरिश में पैसों की तंगी ना हो। ऐसे में आप किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश कर सकते हैं, जो आपके बच्चे की शिक्षा और स्वास्थ्य समेत परिवार की बाकी जरूरतों के लिए कवरेज दे।

वायुसेना को मिलेंगे 97 तेजस, रक्षा मंत्रालय ने HAL को दिया 65 हजार करोड़ का टेंडर

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को 65 हजार करोड़ का टेंडर जारी किया है। इसके तहत एचएएल से 97 एलसीए मार्क 1ए (तेजस) फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे। यह भारत सरकार द्वारा स्वदेशी मिलिट्री हार्डवेयर के लिए दिया गया सबसे बड़ा ऑर्डर हो सकता है। रक्षा मंत्रालय ने एचएएल को टेंडर पर जवाब देने के लिए तीन महीने का समय दिया है। अगर यह डील हो जाती है तो इससे वायुसेना के मिग-21, मिग-23 और मिग-27 जैसे फाइटर जेट्स की जगह भारत में बने एलसीए मार्क 1ए फाइटर जेट्स लेंगे, जो जल्द ही वायुसेना से रिटायर हो जाएंगे। स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा देने की दिशा में यह बेहद अहम कदम है। इससे रक्षा क्षेत्र की छोटी और मध्यम वर्ग की कंपनियों के बिजनेस को भी फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी लगातार एचएएल को बढावा दे रहे हैं और यही वजह है कि सभी प्रकार के स्वदेशी फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और इंजन के निर्माण की डील एचएएल को मिल रही हैं। वायुसेना 83 एलसीए मार्क 1ए का भी दे चुकी है ऑर्डर वायुसेना एचएल को 83 एलसीए मार्क 1ए फाइटर जेट्स का ऑर्डर पहले ही दे चुकी है, जिसके तहत पहला फाइटर जेट कुछ ही हफ्तों में वायुसेना को मिल जाएगा। एलसीए मार्क 1ए, तेजस एयरक्राफ्ट का आधुनिक संस्करण है। 97 एलसीए मार्क 1ए फाइटर जेट्स के सौदे के बारे में भारतीय वायुसेना के चीफ एयरचीफ मार्शल वीआर चौधरी ने स्पेन में पहली बार जानकारी दी थी। हाल ही में वायुसेना चीफ ने स्वदेशी फाइटर जेट्स के प्रोग्राम को लेकर समीक्षा बैठक भी की थी, जिसमें एचएएल के अधिकारी भी शामिल हुए थे।

प्रधानाचार्य को बिजेड़ी प्रचार केलिए साजिस : बीजेपी

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड उडीशा

भुबनेस्वर: राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए 8 अधिकारियों को बदला। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप के बाद राज्य सरकार को सभी सरकारी पोर्टलों से 5 टी का उल्लेख हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।लेकिन, प्रशासन को होश नहीं आया। प्रशासन ने बीती 10 तारीख को पत्र लिखा है। इस पत्र में स्कूलों को मापने के लिए 93 लोगों को नियुक्त किया गया है, जिसमें 93 ब्लॉकों को मेरे 5 स्कूलों में बदल दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से अधिकतर स्वयंसेवक या सलाहकार हैं। लेकिन दरअसल, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बिजेड़ी स्थानीय कार्यकर्ताओं ने यह प्रधान सिख्यक पर बिजेड़ी के पक्ष में काम करने का दबाव बनाने की नापाक साजिश है। बीजेपी की एक प्रतिनिधि मंडली शुक्रवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास लौट आयी है। इस प्रतिनिधि दल का आरोप है कि बिजेड़ी चुनाव प्रचार के लिए सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है। उदाहरण के तौर पर सुंदरगढ़ के एसडीपीओ हिंमाशु भूषण बेहरा और भस्मा थाना प्रभारी राम प्रसाद नाग बीजे के सामान्य कार्यकर्ताओं से अधिक प्रेरित होकर चुनाव में पार्टी का काम कर रहे हैं। ये दोनों लोग विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं।इससे सरकारी अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल उठता है. बीजेपी ने मांग की है कि उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (सी) के तहत मुकदमा चलाया जाए।

बड़बोले पाकिस्तान को जयशंकर ने दिखाया आईना, कहा- बुरे कर्म किए हैं तो फल जरूर मिलेगा

परिवहन विशेष न्यूज

विदेश मंत्री ने कहा कि पड़ोसी मुल्क में अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो इसमें बुरा क्या है। अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं और उन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है।

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को ब्रिटिश अखबार में छपे लेख को लेकर खुलकर टिप्पणी की है। दरअसल, ब्रिटिश अखबार में खुफिया सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान सहित अन्य देशों में मारे गए आतंकियों के पीछे भारत सरकार का हाथ है। पाकिस्तान ने भी मामले में भारत पर आरोप लगाए थे। हालांकि, भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। इस बीच विदेश मंत्री से साक्षात्कार के दौरान इसे लेकर सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि इस पर विदेश मंत्री का जवाब क्या होगा?

विदेश मंत्री ने रिपोर्ट का खंडन करते हुए इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट खुफिया सूत्रों के आधार पर छापी है और भारत क्या कोई भी देश इस तरह की रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं करेगा और करनी भी नहीं चाहिए। फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि पड़ोसी मुल्क में अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो इसमें बुरा क्या है। अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं और उन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। उन्होंने फिर से इस बात पर जोर दिया कि अगर कुछ भी इंटेलिजेंस से जुड़ी रिपोर्ट होती है, तो कोई भी सरकार इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।

रिपोर्ट में क्या कहा गया था?

आपको बता दें कि ब्रिटेन के जानेमाने अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि पाकिस्तान सहित अन्य देशों में मारे गए आतंकियों के पीछे भारत सरकार का हाथ है। ब्रिटिश अखबार ने अपनी खबर में लिखा था कि भारत सरकार ने रणनीति के तहत पाकिस्तान में आतंकवादियों का खात्मा किया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दस्तावेजों में इससे जुड़े कुछ सबूत हैं। हालांकि अखबार ने दस्तावेजों की पुष्टि नहीं की है।

भीलवाड़ा विधानसभा का भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित

भीलवाड़ा में लोकसभा का यह ऐतिहासिक मैच भाजपा जीतेगी, कांग्रेस ऑल आउट होगी – दामोदर अग्रवाल

भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी, कांग्रेस में परिवारवाद हावी रहा – राठौड़

परिवहन विशेष न्यूज

भीलवाड़ा। भारतीय जनता पार्टी भीलवाड़ा विधानसभा का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य, लोकसभा सहप्रभारी गजपाल सिंह राठौड़ के सानिध्य, जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता, विधायक प्रत्याशी विट्ठल शंकर अवस्थी, विधायक अशोक कोठारी, विधानसभा समन्वयक एवं सभापति राकेश पाठक, विधानसभा प्रभारी मदन भंडारी, मंडल अध्यक्ष घनश्याम सिंगीवाल, अनिल सिंह जादौन, पीयूष डाड, मनीष पालीवाल, मिथिलेश बंसल के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित हुआ।

जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि भीलवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने उपस्थित सैंकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भीलवाड़ा में लोकसभा का यह ऐतिहासिक मैच भाजपा जीतेगी और कांग्रेस ऑल आउट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक और राष्ट्रप्रेमी शक्तियां है तो दूसरी ओर राष्ट्र विरोधी शक्तियां। एक और सांस्कृतिक उन्नयन, गरीब कल्याण और विकसित भारत का संकल्प है तो दूसरी ओर जातिवाद, भ्रष्टाचार, अहंकार है। एक और दिल से राजनीति करने वाले भाजपा के कार्यकर्ता है तो दूसरी ओर दिमाग से राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी और समूचा विपक्ष। मतदाताओं को राष्ट्रवाद और सनातन को समर्पित इस चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीताकर 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने होंगे।

सम्मेलन में लोकसभा सहप्रभारी गजपाल सिंह राठौड़ ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं से बनी पार्टी है जबकि कांग्रेस में शुरू से परिवारवाद हावी रहा है, आज इसी वजह से वह पार्टी इस स्थिति में पहुंच गई है। भाजपा को इस बार चार सौ पार पहुंचाने के लिए भीलवाड़ा में भी ऐतिहासिक जीत दर्ज करनी है। जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को एकमुखी और एकजुट होकर लोकसभा चुनाव में भाजपा को भीलवाड़ा में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाने के लिए कार्य करना होगा। विधायक प्रत्याशी विट्ठल शंकर अवस्थी ने कहा कि हम सभी को मिलकर राष्ट्रवाद की भावना के साथ आगे बढ़ना होगा। सभी कार्यकर्ताओं को एकमुखी होकर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए देश के कोने कोने में कमल खिलाना है। विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने भीलवाड़ा सीट के लिए योग्य और श्रेष्ठ कार्यकर्ता को चुना है। ऐसे कार्यकर्ता को अब हमें चुनकर संसद भेजना है, जहां वे भीलवाड़ा की आवाज उठा सके। सभापति राकेश पाठक ने कहा कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से समूचे देश के साथ भीलवाड़ा की आमजनता भी लाभान्वित हो रही है, इसका असर आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा और भाजपा देश में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। सम्मेलन का सफल संचालन जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद त्रिपाठी ने किया। अंत में आभार जिला महामंत्री राजकुमार आंचलिया ने प्रकट किया।

इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष बाबूलाल आचार्य, छैलबिहारी जोशी, अविनाश जीनगर, जिला मंत्री सुरेंद्र सिंह मोटरास, गोपाल तेली, अमित सारस्वत, प्रतिभा माली, जिला कोषाध्यक्ष ललित अग्रवाल, सह कोषाध्यक्ष पंकज मानसिंहका, अध्यक्षीय प्रवास प्रमुख मनोज बुलानी, आइटी जिला संयोजक अजय नौलखा, सोशल मीडिया जिला संयोजक अजीत सिंह केसावत, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कुलदीप शर्मा, एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष पूरण डीडवानिया, एसटी मोर्चा जिलाध्यक्ष महेंद्र मीणा, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष शंकरलाल जाट, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष भगवत सिंह राठौड़, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष इमरान कायमखानी, पूर्व जिलाध्यक्ष एल एन डाड, लादूलाल तेली, रामनाथ योगी, नंदलाल गुर्जर, राजा साध वैष्णव, राहुल सोनी, सुरेश छाजेड़, भैरू मल्होत्रा, ललित व्यास, राजू जांगिड़, पुरषोत्तम बैरवा, सत्यनारायण धोबी, लवकुमार जोशी, पंकज प्रजापत सहित सैंकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

चुनाव प्रचार के दौरान सीएम की बस पर पथराव, जगन मोहन रेड्डी की आंख के ऊपर आई चोट

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी घायल हो गए हैं। विजयवाड़ा में रोड शो के दौरान पथराव के दौरान उन्हें चोट आई है। विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी चुनाव प्रचार के दौरान घायल हो गए। विजयवाड़ा में एक चुनावी यात्रा के दौरान उन्हें चोट आई है। जानकारी के मुताबिक, उनकी यात्रा पर कुछ व्यक्तियों ने पथराव किया। घटना उस वक्त हुई, जब जगन मोहन रेड्डी मेमंता सिद्धम बस यात्रा कर रहे थे। वाईएसआरसीपी ने बताया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने सीएम की बस पर पथराव किया, जिससे उनकी बाईं आंख के ऊपर चोट लग गई।

चोट लगने के बाद डॉक्टरों ने बस के अंदर ही किया प्राथमिक उपचार

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान में बताया गया कि पत्थर सीएम को तब लगा, जब वह विजयवाड़ा के सिंहनगर में विवेकानंद स्कूल सेंटर में यात्रा दौरान भीड़ का अभिनंदन कर रहे थे। अधिकारियों को संदेह है कि इसे गुलेल से लॉन्च किया गया होगा। इसके बाद बस पर सवार लोगों ने सीएम को संभाला और उनकी चोट को रूमाल से ढका। तत्काल मुख्यमंत्री को बस के अंदर ही एक डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार दिया। रेड्डी को बस के अंदर इलाज करते वक्त दर्द से कराहते हुए देखा गया। हालांकि, पथराव से घबराए बिना उन्होंने शहर में अपना दौरा फिर से शुरू कर दिया।

जेपी नड्डा बोले- कांग्रेस की नीति सिर्फ वोट लो और भूल जाओ, इसलिए वे एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाए

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को नागालैंड पहुंचे थे। यहां उन्होंने चुमौकेदिमा में भाजपा समर्थित एनडीपीपी उम्मीदवार चुम्बेन मुरी के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान, पूर्वोत्तर में राजनीति का मतलब फूट डालो और राज करो था।

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस वोट लो और लोगों को भूल जाओ वाली नीति में विश्वास करती है। इस वजह से नागालैंड में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएंगे। वे राज्य में पूर्ण शांति और सद्भाव लाने के प्रयास में नागा समझौते को आगे बढ़ाएंगे।

कांग्रेस ने फूट डालो और राज करो नीति को अपनाया

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को नागालैंड पहुंचे थे। यहां उन्होंने चुमौकेदिमा में भाजपा समर्थित एनडीपीपी उम्मीदवार चुम्बेन मुरी के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान, पूर्वोत्तर में राजनीति का मतलब फूट डालो और राज करो था। भाजपा सरकार सबका साथ-सबका विकास की नीति में विश्वास करती है। हम नागा शांति समझौते को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे। एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान 11 शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया और 9500 विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया।

कांग्रेस को इस वजह से विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिली

नड्डा ने कहा कि कांग्रेस कभी भी समय और उन्हें मिले अवसर का सम्मान नहीं कर पाई। इस वजह से राज्य में विकास और समृद्धि रुक गई। कांग्रेस ने वोट लो और लोगों को भूल जाओ वाली नीति के साथ नागालैंड की प्रगति और समृद्धि में बाधा डाला। कांग्रेस की इसी रणनीति के कारण उन्हें राज्य में एक भी विधानसभा सीट पर जीत नहीं मिली। पीएम मोदी के नेतृत्व में नागालैंड बदलते समय को देख रहा है। पीएम मोदी ने क्षेत्र में राजनीति की संस्कृति, परिभाषा और दृष्टिकोण बदल दिया है। कांग्रेस शासन में पूर्वोत्तर का मतलब बांटो और राज करो। आज दिल्ली के लिए न तो कोहिमा और न ही मणिपुर दूर है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोगों से मुरी के लिए वोट करने का आग्रह करते हुए कहा कि पीएम मोदी हमेशा उनका सम्मान करेंगे। एनडीए सरकार पूरी ताकत से नागालैंड के साथ खड़ी है। हम राज्य के विकास और प्रगति को आगे बढ़ाएगा।

पंजाब जहा हमेशा सनातन धर्म और गुरुद्वारे की बात होती थी वहा अब चर्च और धर्मांतरण की बात होती है, आखिर कोन है जिम्मेदार?

परिवहन विशेष नयूज

विनाश काले विपरीत बुद्धि अब इनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि एक बोरी चावल थोड़े से पैसे का कमाल है। जिस सिख खालसा पंथ की स्थापना हिन्दू धर्म अध्यात्म संस्कृति सभ्यता संस्कार और परम्पराओं के रक्षार्थ के लिए हुआ था वह अब धार्मिक संस्कारों के अभाव के कारण पंजाब में सिख्खी प्रचार-प्रसार में कमी आई। गुरूद्वारों के ग्रंथी ज्ञानी प्रमाद में पड़ कर सामाजिक धार्मिक भावनाओं से समाज को दिशा-निर्देश नहीं दें रहें हैं। प्रपंचों छल-कपट से ग्रस्त चंगाई सभा करके ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मान्तरण किया जा रहा है। पंजाब का दुर्भाग्य तो देखो पहले जहां पंजाब में हर जगह नए नए गुरुद्वारो का निर्माण होते दिखाई देता था वहीं आज पंजाब के हर जिले में चर्च का निर्माण होते दिखाई दे रहा है। पंजाब में पंजाबी ही पंजाबी को धर्मान्तरण कर के ईसाई बना रहा है। पहले पंजाब के लड़के और लड़कियां गुरबाणी गाते थे आज ? आखिर क्यों इतना पंजाब बदल गया और लोग चुपचाप देखते रहे। आधा पंजाब खालिस्तानी बनाने वाले खा गए और बाकी बचा आधा ईसाई खा रहे है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023